www.deshbandhu.co.in खबरें लगातार ...

पत्र नहीं; मित्र

संपर्क : deshbandhubpl1@gmail.com

देशबन्धु

वर्ष – 37 । अंक –216 । भोपाल, शुक्रवार, 7 अगस्त 2026 । पृष्ठ–8 । मूल्य – 2.00 रुपए

आज से हर शुक्रवार फील्ड में उतरेगा पूरा प्रशासन — पृष्ठ 2

भारत में बढ़ती असमानता और सिकुड़ते अवसर — पृष्ठ 4

डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन : भारत की हरित क्रांति के जनक — पृष्ठ 4

कलेक्टर की पहल से 726 बालिकाओं को मिला लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ — पृष्ठ 6

आरकेएमपी पर कचरा प्रबंधन में लापरवाही पर एनजीटी ने संबंधितों को लगाई फटकार — पृष्ठ 7

सार-समाचार

मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का सफल परीक्षण

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल 'अग्नि-4' का गुरुवार को सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह परीक्षण ओडिशा की चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया। सामरिक बल कमान की देख-रेख में किये गये परीक्षण के दौरान सभी संचालन और तकनीकी मानकों की पुष्टि हुई। यह मिसाइल 4,000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है और एक टन वजनी परमाणु हथियार ले जा सकती है। सतह से सतह पर मार करने वाली इस मिसाइल से देश की रणनीतिक रक्षा और प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी।

नीरज डांगी राज्यसभा में कांग्रेस संसदीय दल के सचेतक नियुक्त

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राज्यसभा सदस्य नीरज डांगी को राज्यसभा में कांग्रेस संसदीय दल का सचेतक (व्हिप) नियुक्त किया है। कांग्रेस संसदीय दल ने गुरुवार को यहां एक बयान में यह जानकारी देते हुए बताया कि श्री डांगी को राज्यसभा में कांग्रेस संसदीय दल का सचेतक बनाया गया है। राज्यसभा सदस्य रजनी अशोकराव पाटिल के सेवानिवृत्त होने से यह पद रिक्त हुआ है। श्री डांगी की नियुक्ति राज्यसभा सदस्य श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल के सेवानिवृत्त होने से रिक्त हुए सचेतक के पद पर की गई है।

झारखंड : दलमा में बड़ी नक्सली साजिश नाकाम

सरायकेला, एजेंसी। झारखंड के दलमा जंगल क्षेत्र में माओवादियों की नई गतिविधियों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सरायकेला-खरसावां के पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गियारी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि सारंडा क्षेत्र में सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई के बाद माओवादी संगठन दलमा इलाके में फिर से अपना नेटवर्क खड़ा करने और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में था। संयुक्त अभियान चलाकर इस साजिश को नाकाम कर दिया गया है। इस दौरान तीन इनामी नक्सलियों की गिरफ्तारी की गई है और उनकी निशानदेही पर दलमा पहाड़ से हथियारों का जखीरा भी बरामद किया गया है।

सड़क हादसे में अतीक अहमद के छोटे बेटे की मौत

झांसी, एजेंसी। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में गुरुवार को माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान अहमद समेत दो लोगों की भीषण सड़क हादसे में मौत हो गई जबकि कई गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है सभी कार सवार प्रयागराज से झांसी जेल में बंद अतीक के बड़े बेटे अली अहमद से मुलाकात करने जा रहे थे। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार कार के अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने की बात सामने आई है। पुलिस के अनुसार, हादसा झांसी-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पूछ थाना क्षेत्र के के पास हुआ। प्रयागराज से झांसी आ रही क्रेटा कार अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि हादसे में अतीक के बेटे अबान समेत दो की मौत हो गई। अन्य घायलों को तत्काल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सभी प्रयागराज के निवासी बताए गए हैं।

दूषित पेयजल से बच्ची की मौत पर एनएचआरसी का ने लिया संज्ञान

नई दिल्ली, एजेंसी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने हरियाणा के अंबाला जिले के शाहजादपुर में दूषित पेयजल के सेवन से पीलिया होने के कारण 12 वर्षीय बच्ची की मौत के मामले का स्वत: संज्ञान लिया है। एनएचआरसी ने गुरुवार को बताया कि आयोग ने मामले को गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़ा मानते हुए हरियाणा के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। तीन अगस्त को प्रकाशित खबर में बताया गया था कि 12 वर्षीय बच्ची का पहले स्थानीय अस्पताल में पीलिया का इलाज किया गया था।

राज्यसभा में विपक्ष के नेता ने कहा प्रधानमंत्री व गृहमंत्री सदन में आकर बयान दें

संसद को बाधित करने के लिए सत्तापक्ष जिम्मेदार : खरगे

- सरकार विपक्ष को अपनी बात भी नहीं रखने देती
- कांग्रेस पूरे देश के छात्रों और युवाओं के साथ खड़ी

नई दिल्ली, देशबन्धु। कांग्रेस अध्यक्ष तथा राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने संसद में गतिरोध के लिए सत्तापक्ष को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मामले में सदन में आकर जवाब देंगे तब ही संसद सुचारु रूप से चल सकेगी। श्री खरगे ने गुरुवार को यहां अपने आवास 10 राजाजी मार्ग पर संवाददाताओं से कहा कि विपक्ष पिछले 15 दिनों से छात्रों पर हुए कथित अत्याचार, लाठीचार्ज, पैलेट गन और आंसू गैस के इस्तेमाल के मुद्दे पर गृह मंत्री से सदन में बयान देने की मांग कर रहा है लेकिन सरकार लगातार इससे बच रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्र शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे, इसके बावजूद उनके खिलाफ बल प्रयोग किया गया और इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि विपक्ष केवल यह जानना चाहता है कि छात्रों पर लाठीचार्ज, पेलेट गन और आंसू गैस के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया। यदि गृह मंत्री सदन में आकर स्थिति स्पष्ट कर देते तो इस मुद्दे पर चर्चा हो जाती और संसद का कामकाज सामान्य रूप से चल सकता था।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि राज्यसभा के सभापति ने भी संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू से कहा है कि सदन की इच्छा है कि गृह मंत्री सदन में आकर अपनी बात रखें लेकिन इसके बावजूद सरकार ने इस दिशा में कोई पहल नहीं की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष को अपनी बात रखने का अवसर भी नहीं देती और जनता से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर जवाबदेही से बच रही है।

छात्रों की आवाज उठाती रहेगी पार्टी

श्री खरगे ने कहा कि विपक्ष संसद को बाधित करने की बजाय चाहता है कि सदन में सार्थक चर्चा हो। यदि श्री मोदी छात्रों और उनके अभिभावकों से माफी मांग लें तथा श्री शाह सदन में बयान दे दें तो संसद का गतिरोध समाप्त हो सकता है। झारखंड में छात्रों से जुड़े घटनाक्रम के बारे में पूछे गए एक सवाल पर श्री खरगे ने कहा कि कांग्रेस किसी एक राज्य की नहीं, बल्कि पूरे देश के छात्रों और युवाओं के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि झारखंड, पंजाब, दिल्ली या किसी भी राज्य में छात्रों के साथ अन्याय होगा तो कांग्रेस उनकी आवाज उठाती रहेगी और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष जारी रखेगी।

पुलिस बर्बरता व चढ़ावा चोरी पर फिर हुआ हंगामा

नई दिल्ली, एजेंसी। छात्रों पर पुलिस बर्बरता और मंदिर चढ़ावा चोरी मुद्दों को लेकर 14 वे दिन में संसद में भारी हंगामा हुआ, जिसके चलते दोनों सदनों कार्यवाही बाधित हुई। राज्यसभा में जब विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे बोलने के लिए खड़े हुए तो भाजपा के सांसदों ने टोका टाकी शुरू की जिसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। बाद में उन्होंने कहा कि वे दो ही चीज चाहते हैं, पहला गृह मंत्री अमित शाह सदन में आ कर बयान दें कि बच्चों पर लाठी और पैलेट गन क्यों चली? दूसरे प्रधानमंत्री मोदी माफी मांगे। खरगे के मुताबिक राज्यसभा के सभापति ने संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू से कहा है कि सबकी इच्छा है कि गृह मंत्री सदन में आकर बोलें। वहीं जब रिजिजू से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सभापति ने निर्देश नहीं दिया है, बल्कि यह कहा है कि विपक्ष ऐसा चाहता है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री सुबह से शाम तक संसद में ही रहते हैं, लेकिन विपक्ष हंगामा कर रहा है। सदन में तो वही मंत्री उपस्थित रहेगा, जिसके विधेयक पर चर्चा होनी है। गतिरोध खत्म करने के लिए सरकार और विपक्ष के बीच बात तो हो रही है, लेकिन तना तनी भी बरकरार है।

सूरज की ताकत से ऊर्जा के नए शिखर पर मध्य प्रदेश

- नवकरणीय ऊर्जा में देश का अग्रणी राज्य बन रहा प्रदेश : डॉ. यादव
- 438 मेगावाट से बढ़कर 11 हजार मेगावाट हुई क्षमता
- अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में प्रस्तुत किया हरित ऊर्जा मॉडल

भोपाल/ नई दिल्ली, देशबन्धु। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश वर्ष 2030 तक देश की 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता के राष्ट्रीय लक्ष्य को हासिल करने में पूरी प्रतिबद्धता के साथ योगदान दे रहा है। नवकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा भंडारण और हरित औद्योगिक विकास के क्षेत्र में प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है।

नई दिल्ली में आयोजित 7वें अंतरराष्ट्रीय नवकरणीय ऊर्जा सम्मेलन एवं प्रदर्शनी-2026 में मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश की स्वच्छ ऊर्जा उपलब्धियों और भविष्य की कार्ययोजना का प्रस्तुतिकरण किया। सम्मेलन में शामिल होने के लिए उन्होंने एयरपोर्ट से दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन से शिवाजी स्टेडियम तक यात्रा कर स्वच्छ एवं पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन का संदेश भी दिया।

मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में मध्य प्रदेश की नवकरणीय ऊर्जा क्षमता 438 मेगावाट से बढ़कर करीब 11 हजार मेगावाट हो गई है। यानी क्षमता में लगभग 25 गुना वृद्धि हुई है। पिछले दो वर्षों में नवकरणीय ऊर्जा, पंप्ड हाइड्रो ऊर्जा भंडारण और बायोमास से जुड़ी नीतियां लागू कर निवेश और नवाचार को गति दी गई है। उन्होंने कहा कि 750 मेगावाट रीवा अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना ने देश में पहली बार सौर ऊर्जा का टैरिफ कोयला आधारित बिजली से भी कम करने का उदाहरण पेश किया। परियोजना को वर्ल्ड बैंक ग्रुप प्रेसिडेंट्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस मिला है। वहीं 1500 मेगावाट आगर-शाजापुर-नीमच सौर परियोजना में 2.14 रुपये प्रति यूनिट का रिकॉर्ड न्यूनतम सौर टैरिफ हासिल हुआ है।

डॉ. यादव ने बताया कि 278 मेगावाट क्षमता की देश की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना का लोकार्पण 25 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। 'सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना' के तहत करीब 14,900 मेगावाट क्षमता के प्रस्ताव मिले हैं।

ऊर्जा सुरक्षा के लिए मुरैना में 440 मेगावाट सौर ऊर्जा और 880 मेगावाट-घंटा बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजना विकसित की जा रही है। चार, छह और 24 घंटे की सौर-सह-ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं पर भी काम जारी है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रदेश में करीब 1.5 लाख घरों में 566 मेगावाट क्षमता के रूफटॉप सौर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं।

हरित ऊर्जा के क्षेत्र में मप्र के काम की दुनिया में चर्चा : मुख्यमंत्री

भोपाल, देशबन्धु। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश हरित ऊर्जा के क्षेत्र में देश में सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है। सौर और पवन ऊर्जा के उत्पादन को लगातार बढ़ाया जा रहा है। राज्य में चौबीसों घंटे स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने की दिशा में भी काम जारी है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के हरित ऊर्जा मॉडल की चर्चा अब विश्व स्तर पर हो रही है।

नवकरणीय ऊर्जा सम्मेलन एवं प्रदर्शनी में शामिल होने के बाद मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा में मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश भारतीय रेलवे सहित आठ राज्यों को हरित ऊर्जा की आपूर्ति कर रहा है। डॉ. यादव ने बताया कि पिछले दो वर्षों में राज्य सरकार ने नवकरणीय ऊर्जा, पंप्ड हाइड्रो ऊर्जा भंडारण और बायोमास से जुड़ी नीतियां लागू कर निवेश और नवाचार को गति दी है। आगर-शाजापुर-नीमच सौर परियोजना में 2.14 रुपये प्रति यूनिट का रिकॉर्ड न्यूनतम सौर टैरिफ प्राप्त हुआ है।

छात्र आंदोलनों पर बोले मोहन भागवत

जेन-जी हमारी पीढ़ी से ज्यादा ईमानदार

- आरएसएस प्रमुख ने कहा वे देशविरोधी नहीं, उनकी शिकायतें वास्तविक
- विरोध-प्रदर्शन भी सहमति बनाने का माध्यम

मुंबई, एजेंसी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक मोहन भागवत ने हालिया छात्र आंदोलनों और जेन जी को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि जेन जी विरोध-प्रदर्शन कर रही है तो उन्हें 'देशविरोधी' नहीं कहा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह देश की अपनी नई पीढ़ी है और उनके मुद्दों को संवाद के जरिए समझकर समाधान निकालने की जरूरत है। एक छात्र संवाद कार्यक्रम में भागवत ने कहा, 'अगर जेन जी प्रदर्शन कर रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि वे एंटी-नेशनल हैं। वे हमारे अपने लोग हैं, हमारी अगली पीढ़ी हैं। मेरा मानना है कि जेन जी और जेन अल्फा मौजूदा पीढ़ी की तुलना में अधिक ईमानदार हैं। उनके साथ देशभक्ति और सेवा की ईमानदार अपील प्रभावी होती है।'

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विरोध-प्रदर्शन भी सहमति बनाने का एक माध्यम है। विभिन्न विचारों के बीच संवाद से ही व्यापक सहमति बनती है। यदि किसी कारण से लोगों की बात नहीं सुनी जाती, तब आंदोलन का रास्ता अपनाया जा सकता है, लेकिन उसका उद्देश्य समाज में विभाजन पैदा करना नहीं, बल्कि व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। भागवत ने कहा कि हाल की घटनाओं में छात्रों की शिकायतें वास्तविक हैं और भारत की शिक्षा व्यवस्था में अभी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इसलिए इन मुद्दों पर गंभीर संवाद होना चाहिए।

सभी के लिए शिक्षा सुलभ होनी चाहिए

शिक्षा व्यवस्था पर बोलते हुए भागवत ने कहा कि शिक्षा सभी के लिए सुलभ होनी चाहिए और उसकी उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सबसे पहले शिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, 'शिक्षा हमारे बच्चों और अगली पीढ़ी के निर्माण के लिए है, पैसा कमाने का माध्यम नहीं।' उन्होंने शिक्षकों के लगभग 10 लाख रिक्त पदों का उल्लेख करते हुए शिक्षा पर सकल बजट का 6 प्रतिशत खर्च किए जाने की लंबे समय से चली आ रही मांग का समर्थन किया।

उन्होंने कहा, 'जब हम उनकी उम्र के थे, तब बड़ों की हर बात बिना सवाल किए मान लेते थे।

सीजेपी सितंबर से देशभर में चलाएगी 'बोलती पब्लिक' अभियान

नई दिल्ली, देशबन्धु। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने जंतर-मंतर आंदोलन और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को युवाओं की बड़ी जीत बताते हुए पार्टी के आगामी एजेंडे का ऐलान किया। दिपके ने गुरुवार को कहा कि पिछले कई वर्षों से सरकार यह संदेश देती रही कि सत्ता में बैठे लोगों से कोई सवाल नहीं पूछ सकता। लेकिन युवाओं के आंदोलन ने इस धारणा को बदल दिया। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सिर्फ एक व्यक्ति का इस्तीफा नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक आंदोलन की सफलता और जनता के भीतर से डर खत्म होने का प्रतीक है।

कॉकरोच जनता पार्टी की विचारधारा पर बोलते हुए दिपके ने कहा कि उनकी पार्टी भारतीय संविधान के मूल्यों पर चलने वाली पार्टी है। उन्होंने कहा कि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों से प्रेरित होकर पार्टी सामाजिक न्याय, लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए काम करेगी। दिपके ने बताया कि पार्टी की दो दिवसीय कोर कमेटी की बैठक में सितंबर से देशभर में 'बोलती पब्लिक' नाम से राष्ट्रीय अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है।

विमान ईंधन में एथेनॉल मिलाने की कोई योजना नहीं : नायडू

- मीडिया पर आई खबरों को गलत बताया
- केजरीवाल ने भी सवाल उठाए थे

नई दिल्ली, एजेंसी। नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू ने गुरुवार को कहा कि विमान ईंधन में एथेनॉल मिलाने की योजना के दावों को गलत बताया और कहा कि इससे हवाई यात्रियों में अनावश्यक चिंता पैदा होती है। श्री नायडू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि सरकार द्वारा विमान ईंधन में एथेनॉल मिलाने की योजना होने का दावा 'पूरी तरह से झूठा और गैर-जिम्मेदाराना' है। उन्होंने कहा कि ऐसी किसी भी योजना का प्रस्ताव नहीं है। उल्लेखनीय है कि मीडिया में इस तरह की खबरें आयी थीं कि सरकार ने विमान ईंधन में एथेनॉल मिलाने की अनुमति दे दी है।

इसके बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी सोशल मीडिया पर कहा कि इससे विमान का इंजन कभी भी बंद हो सकता है और यात्रियों की जान का खतरा हो सकता है। श्री नायडू ने स्पष्ट किया कि हरित विमान ईंधन एथेनॉल से अलग है। उन्होंने लिखा, 'एथेनॉल और हरित विमान ईंधन पूरी तरह अलग-अलग ईंधन हैं और इन्हें एक-दूसरे के समान नहीं माना जाना चाहिए। हरित विमान ईंधन एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित विमानन ईंधन है, जिसे अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त है और दुनिया भर में अपनाया गया है। यह कठोर परीक्षणों से गुजरता है और वैश्विक सुरक्षा के सख्त मानकों पर खरा उतरता है।" नागरिक उड्डयन मंत्री ने यात्रियों की सुरक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा कि विमानन सुरक्षा से जुड़ी गलत जानकारी फैलाने से केवल हवाई यात्रियों में अनावश्यक चिंता पैदा होती है।

अमेरिका का दुनिया के 60 फीसदी तेल पर नियंत्रण : ट्रंप

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका का दुनिया के 60 प्रतिशत तेल पर कंट्रोल है, जिसमें वेनेजुएला के रिसोर्स को भी अमेरिकी क्षमता का हिस्सा माना गया है। लास वेगास में अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए श्री ट्रंप ने कहा, 'हमारे पास दुनिया के किसी भी देश की तुलना में ज़्यादा तेल और गैस है। अब इसमें वेनेजुएला को भी जोड़ लें। इसे जोड़ने पर, वेनेजुएला सहित हमारे पास दुनिया का 60 प्रतिशत तेल और गैस है।'

अमेरिका ने 3 जनवरी को वेनेजुएला में एक बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया, जिसके दौरान निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को हिरासत में लेकर न्यूयॉर्क ले जाया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन पर 'नार्को-टेररिज्म' (नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़ा आतंकवाद) में शामिल होने के आरोपों के लिए मुकदमा चलाया जाएगा। मादुरो और फ्लोरेस ने न्यूयॉर्क की अदालत में आरोपों से इनकार किया। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद, वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी रूप से राष्ट्रपति पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति रोड्रिग्ज को सौंप दिया। उनके कार्यकाल के दौरान, अमेरिकी और वेनेजुएला के अधिकारियों ने एक नए द्विपक्षीय एजेंडे पर बातचीत शुरू की है, जिसमें ड्रग तस्करी से निपटने में सहयोग, वेनेजुएला के फंड की रिहाई, दक्षिण अमेरिकी देश के तेल की बिक्री, माइनिंग एक्सप्लोरेशन और राजनयिक बातचीत को फिर से शुरू करना शामिल है।

निचली अदालत ने सही से नहीं की जांच, उच्च न्यायालय बना रहा मूकदर्शक

22 साल जेल में रहा बेगुनाह, सर्वोच्च अदालत ने निचली अदालतों को फटकारा

नई दिल्ली, देशबन्धु। न्यायिक संस्थाओं की कमजोरी कभी-कभी किसी जिन्दगी के साथ ऐसा खिलवाड़ कर देती है कि जब बेकसूर आदमी भी उम्रकैद जैसी सजा काटने के लिए मजबूर हो जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐसे शख्स को बरी किया है, जिसे अपनी जिंदगी के 22 साल जेल में गुजारने पड़े।

यह सब उसे ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट की वजह से भुगतना पड़ा। क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने सबूतों की सही से जांच नहीं की और दोषी ठहराए जाने के बाद हाई कोर्ट ने उसकी अपील पर सुनवाई नहीं की, यानी उच्च न्यायालय मौन बना रहा। जिसके बाद उसने शीर्ष अदालत में गुहार लगाई। यह एक ऐसा विशिष्ट मामला है जहां एक गरीब वादी का न्याय के लिए संघर्ष न्यायपालिका के ही हाथों विफल हो गया, जब अदालत ने तकनीकी आधार पर सुनवाई से इनकार कर दिया। गरीब दोषी पहले ही 12 साल जेल में बिता चुका था, जब उसने उच्च न्यायालय का रुख किया। न्यायालय ने अपील दायर करने में देरी के तकनीकी आधार पर उसकी सुनवाई करने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट के इनकार करने के बाद उसे 10 साल और जेल में गुजारना पड़ा।

सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा-

जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो शीर्ष अदालत ने तमाम बिंदुओं पर ध्यान देते हुए उसे बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट को यह स्वीकार करना पड़ा कि- न्याय तक पहुंच अभी भी हमारे समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों और विशेष रूप से उनमें से दोषी ठहराए गए और जेल में बंद लोगों से दूर है । जस्टिस जेबी परदीवाला और के विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा, 'हम उस आदेश से बेहद निराश और चिंतित हैं, जिसमें 3,157 दिनों की देरी की माफी मांगने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया और परिणामस्वरूप धारा 302 के तहत दोषसिद्धि के आदेश के खिलाफ 'जेल अपील ज्ञापन' को भी खारिज कर दिया गया, जिसमें दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, जबकि विवादित आदेश के समय वह 12 साल और अब 10 साल की अतिरिक्त अवधि, कुल मिलाकर 22 साल जेल में बिता चुका था। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि हाईकोर्ट को इस बात पर भी विचार करना चाहिए था कि यह जेल के माध्यम से अपील थी और न्यायालय को इस मामले का व्यावहारिक दृष्टिकोण, या बल्कि सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना चाहिए था और कम से कम याचिकाकर्ता को अपनी आपराधिक अपील पर गुण-दोष के आधार पर बहस करने का एक अवसर देने के लिए देरी को माफ कर देना चाहिए था। सबूतों की जांच करने पर अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि यह मामला केवल एक प्रत्यक्षदर्शी के अविश्वसनीय और संदिग्ध बयान के आधार पर दोष सिद्ध करने योग्य नहीं था। जिसके बाद अदालत ने उसे तिहरे हत्याकांड के मामले में बरी कर दिया।

शीर्ष अदालत ने कहा कि केवल संदेह के आधार पर व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। उससे थर्ड डिग्री (यातना) देकर इकबालिया बयान लिया गया, जिसे कानून में सबूत के तौर पर स्वीकार भी नहीं किया जा सकता था। इसके बावजूद ट्रायल कोर्ट ने सबूतों की सही तरीके से जांच नहीं की और हाई कोर्ट भी मूकदर्शक बना रहा। जिसके चलते बिना किसी मजबूत सबूत के उस व्यक्ति की जिंदगी के 22 साल बर्बाद हो गए।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का महत्वाकांक्षी जन-विश्वास अभियान

आज से हर शुक्रवार फील्ड में उतरेगा पूरा प्रशासन

भोपाल, देशबन्धु। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की जनोन्मुखी पहल के तहत जन-विश्वास अभियान का शुभारंभ 7 अगस्त से होगा। अभियान के तहत हर शुक्रवार मंत्रालय से लेकर जिले तक के अधिकारी दफ्तर छोड़कर फील्ड में पहुंचेंगे और जनता से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं और शिकायतों का समाधान करेंगे। अभियान के चार प्रमुख स्तंभ संवाद, समाधान, संवेदनशीलता और सादगी होंगे।

अभियान के दौरान शुक्रवार को अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर किसी भी स्तर पर बैठक आयोजित नहीं होगी। मुख्यमंत्री, मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार फील्ड में पहुंचेंगे। कलेक्टर एक सप्ताह पहले भ्रमण क्षेत्र चिन्हित कर जनप्रतिनिधियों को जानकारी देंगे।

भ्रमण से पहले संबंधित क्षेत्र की सीएम हेल्पलाइन, जनसुनवाई और लोक सेवा गारंटी के लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर शत-प्रतिशत निराकरण का प्रयास किया जाएगा। मौके पर प्राप्त नए आवेदनों का भी यथासंभव तत्काल समाधान होगा।

अभियान में जन-संवाद के साथ उद्योग संवाद भी होगा। एमएसएमई और कुटीर उद्योगों से जुड़े उद्यमियों की समस्याओं का मौके पर निराकरण किया जाएगा। अविवादित नामांतरण, सीमांकन और बंटवारे के लंबित राजस्व प्रकरणों के साथ न्यायालयीन आदेशों के अमल से जुड़े मामलों का भी समाधान किया जाएगा।

किसानों के लिए फार्मर आईडी, खाद-बीज की उपलब्धता, आयुष्मान कार्ड और समग्र आईडी की ई-केवाईसी जैसे मामलों की समीक्षा होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र परिवारों, जल जीवन मिशन, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य केंद्रों और स्कूल-कॉलेजों का निरीक्षण भी अभियान का हिस्सा रहेगा।

अधिकारी राशन दुकान, तहसील, मंडी, पुलिस थाना, लोक सेवा केंद्र, सड़क, तालाब और अन्य शासकीय परिसंपत्तियों की स्थिति भी जांचेंगे। कानून व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की पहुंच की समीक्षा होगी। अभियान को सादगी और मितव्ययिता के साथ संचालित किया जाएगा।

छिंदवाड़ा से आज करेंगे `मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान 2026´ का शुभारंभ

छिन्दवाडा, देशबन्धु। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 7 अगस्त को छिंदवाड़ा प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान 2026 का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ.यादव के मुख्य आतिथ्य में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय समाधान कार्यक्रम में सीएम हेल्पलाइन सहित विभिन्न जनशिकायतों एवं आवेदनों के निराकरण की समीक्षा की जाएगी। कार्यक्रम की समस्त कार्यवाही सीएम हेल्पलाइन पोर्टल के माध्यम से संपादित की जा रही है।

बच्चों की सुरक्षा को लेकर श्वेत पत्र जारी करे सरकार

भोपाल, देशबन्धु। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश में बच्चों के अपहरण और गुमशुदगी के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखा है। उन्होंने सरकार से बच्चों की सुरक्षा को लेकर तत्काल प्रभावी कदम उठाने और इस बारे में श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

पटवारी ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा किसी भी राज्य की कानून-व्यवस्था का सबसे संवेदनशील पैमाना होती है, लेकिन मध्यप्रदेश में इस संबंध में हालात लगातार चिंताजनक होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को पारदर्शिता के साथ स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समयबद्ध कार्ययोजना लागू करनी चाहिए। पत्र में पटवारी ने मांग की है कि प्रत्येक जिले में ऐसे मामलों की मासिक सार्वजनिक समीक्षा की जाए और लंबित मामलों के लिए विशेष अभियान शुरू हो। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस, रेलवे पुलिस और बाल संरक्षण संस्थाओं के बीच समन्वित तंत्र विकसित करना, मानव तस्करी और संगठित गिरोहों की जांच के लिए संयुक्त टास्क फोर्स का गठन किया जाए।

दतिया उपचुनाव में निभाई थी अहम भूमिका

अवधेश नायक प्रदेश कांग्रेस महासचिव नियुक्त

भोपाल, देशबन्धु। दतिया विधानसभा उपचुनाव में अहम भूमिका निभाने वाले पार्टी नेता अवधेश नायक को प्रदेश कांग्रेस का महासचिव नियुक्त किया गया है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी के अनुमोदन के बाद उनके नियुक्ति आदेश जारी किए हैं।

उल्लेखनीय है कि दतिया उपचुनाव के समय अवधेश नायक का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा था। उन्होंने मतदाताओं से सीधे जनसम्पर्क से लेकर सोशल मीडिया तक जमकर पार्टी के पक्ष में प्रचार किया था।

साल 2023 में पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा से मतभेदों के चलते नायक भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इसके बाद उन्हें कांग्रेस ने टिकट दिया था, लेकिन कुछ समय बाद ही कांग्रेस ने उनकी जगह राजेंद्र भारती को मैदान में उतार दिया था, जिन्होंने जीत हासिल की थी।

इस बार भी नायक कांग्रेस से टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन पार्टी ने उनकी जगह पूर्व विधायक घनश्याम सिंह को टिकट दे दिया। इसके बाद से उनकी नाराजगी की खबरें आ रही थीं।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष नायक को मनाने के लिए उनके निवास पहुंचे थे। इसे बाद से वे पूरी तरह चुनाव प्रचार में जुट गए थे। चुनाव में घनश्याम सिंह ने 6016 वोटो से जीत हासिल की थी।

सार-समाचार

धर्म बदलने पर पांच साल कैद, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बहनों को कराया मुक्त

प्रयागराज, एजेंसी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दो बालिग बहनों को कथित रूप से करीब पांच साल तक घर में रोके रखने के मामले में उन्हें तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है। दोनों महिलाओं ने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाया था। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति संदीप जैन की एकल पीठ ने की। हेबियस कॉर्पस याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि किसी बालिग व्यक्ति की धार्मिक पसंद और निजी स्वतंत्रता में परिवार या अन्य किसी व्यक्ति को हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। अदालत ने महिलाओं की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अदालत ने मामले में माता-पिता और उत्तर प्रदेश सरकार को संयुक्त रूप से 25 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश भी दिया। पुलिस को महिलाओं की जिंदगी और उनकी पसंद में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करने की हिदायत दी गई। अदालत ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को संविधान के अनुच्छेद 21 से जोड़ते हुए कहा कि बालिग व्यक्ति को अपनी जिंदगी और पसंद के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार है।

डॉ. कामले कांग्रेस के संपत्ति विभाग के अध्यक्ष नियुक्त

भोपाल, देशबन्धु। कांग्रेस द्वारा संगठनात्मक पुनर्गठन की प्रक्रिया के तहत, कल प्रदेश कांग्रेस के विभिन्न प्रकोष्ठों एवं विभागों की कार्यकारिणी को भंग किए जाने के बाद आज पुनर्गठन की शुरुआत करते हुए संगठन महामंत्री डॉ. संजय कामले को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के परिसंपत्ति एवं संपत्ति विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा की गई है। इसी कड़ी में आगामी दिनों में प्रदेश कांग्रेस के सभी विभागों एवं प्रकोष्ठों की नई कार्यकारिणियों की भी चरणबद्ध घोषणा की जाएगी।

सरकार से वार्ता के लिए छात्रों ने 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल घोषित किया

रांची, एजेंसी। जेपीएससी, जेएसएससी समेत विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जारी छात्र आंदोलन के बीच राज्य सरकार के साथ प्रस्तावित वार्ता को लेकर आंदोलनकारियों ने गुरुवार को 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की घोषणा कर दी। प्रतिनिधिमंडल में आठ छात्र प्रतिनिधियों के अलावा दो पत्रकार और एक अधिवक्ता को शामिल किया गया है।

बस किराये में भारी बढ़ोतरी जन विरोधी

भोपाल, देशबन्धु। विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने राज्य सरकार द्वारा बसों के किराए में की गई भारी बढ़ोतरी का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने सरकार के इस फैसले को जनविरोधी कदम बताया है। श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने निजी बस संचालकों के आगे घुटने टेक दिए हैं और करोड़ों नागरिकों, छात्रों, किसानों और मजदूरों के हितों को ताक पर रख दिया है। उन्होंने मांग की है कि परिवहन विभाग द्वारा जारी इस जनविरोधी आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। श्री सिंह ने एक बयान में कहा कि नए नियमों के तहत अब सामान्य बसों का मूल किराया सवा रुपये से बढ़ाकर सीधे 2 रुपये प्रति किलोमीटर कर दिया गया है। इसके अलावा न्यूनतम किराया भी ७ रुपये से बढ़ाकर सीधे १० रुपये कर दिया गया है, जिससे गरीब जनता को सबसे बड़ा झटका लगा है। सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों की बसों में की गई यह मनमानी बढ़ोतरी मध्यमवर्गीय परिवारों की कमर तोड़ देगी।

कांग्रेस स्थानीय मुद्दों पर आंदोलन की बनाएगी रणनीति

राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक 11 को होगी

भोपाल, देशबन्धु। कांग्रेस स्थानीय मुद्दों पर आंदोलन और संगठन को मजबूत करने के लिए नए सिरे से रणनीति तैयार करेगी। इसके लिए पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक 11 अगस्त को भोपाल में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित अन्य सदस्य शामिल होंगे। पार्टी के मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने मीडिया को बताया कि कांग्रेस अब राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के मुद्दों के साथ-साथ गांव से लेकर शहर तक के स्थानीय जनसरोकारों को भी प्रमुखता से जनता के बीच ले जाएगी। राजनीतिक मामलों की समिति की

बैठक में इसकी विस्तृत रूपरेखा तैयार की जाएगी। नायक ने कहा कि भाजपा सरकार जनविरोधी नीतियां अपना रही है। जिससे किसान युवा सब परेशान हैं। भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के साथ ही स्थानीय स्तर पर व्याप्त समस्याओं के चलते आम लोगों में असंतोष व्याप्त है। उन्होंने नगर निगमों और नगर पालिकाओं में भ्रष्टाचार तथा पेयजल व्यवस्था को लेकर भी सरकार को घेरा। नायक ने कहा कि कई स्थानों पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। सहकारिता, खेल और अन्य संस्थाओं का राजनीतिक दुरुपयोग किया जा रहा है। पुलिस प्रतिशोध की भावना से काम कर रही है। कांग्रेस नेताओं को लगातार जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा जारी वीडियो पर गोपाल भार्गव ने किया पलटवार, बोले-

वीडियो को शेयर करने से पहले तथ्यों की जांच करें

भोपाल, देशबन्धु। कोपरा नदी को लेकर आए एक वीडियो पर प्रदेश की सियासत गर्म हो गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो के बाद वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने पलटवार करते हुए दावा किया है कि वीडियो की वास्तविक स्थिति अलग है और इसे बिना पूरे तथ्य जाने सार्वजनिक किया गया। भार्गव ने पटवारी को ये नसीहत भी दी कि किसी भी वीडियो शेयर करने से पहल वे तथ्यों की जांच करें। भार्गव ने कहा कि विपक्ष का काम सरकार से सवाल पूछना और जनता के मुद्दे उठाना है, लेकिन यह जिम्मेदारी तथ्यों के आधार पर निभाई जानी चाहिए।

दरअसल, एक वीडियो भार्गव के विधानसभा क्षेत्र में पुल निर्माण और छात्राओं के आवागमन को लेकर है। इस पर भार्गव ने कहा कि जिस स्थान का वीडियो साझा किया गया है, वहां

पहले से पुल निर्माण का काम जारी है और प्रशासन की ओर से वैकल्पिक रास्ते भी उपलब्ध हैं। उनके मुताबिक केवल एक वीडियो के आधार पर पूरे क्षेत्र की स्थिति पर निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले नेताओं को किसी भी मुद्दे पर प्रतिक्रिया देने से पहले स्थानीय स्थिति और आधिकारिक जानकारी की पुष्टि करनी चाहिए।

भार्गव ने बताया कि लोक निर्माण मंत्री रहते हुए उन्होंने जून 2023 में सागर जिले के बेरखेरी कलां-छुल्ला मार्ग पर कोपरा नदी पर करीब 10 करोड़ रुपये की लागत से 100 मीटर लंबे हाई लेवल पुल को मंजूरी दी थी। उनके अनुसार भूमि विवाद के कारण परियोजना कुछ समय तक प्रभावित रही, लेकिन अब मामला सुलझ चुका है और निर्माण कार्य जारी है। उन्होंने यह भी कहा कि पुराने पुल के क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत कर गैप फिलिंग की गई है ताकि लोगों का आवागमन पूरी तरह बाधित न हो।

भार्गव ने अपने विधानसभा क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों का भी जिक्र किया। उनके अनुसार सुनार नदी पर 18 किलोमीटर के दायरे में 10 पुल बनाए गए हैं, जबकि ग्राम चौरई में एक परिवार की सुविधा के लिए भी लगभग 10 करोड़ रुपये की लागत से पुल का निर्माण कराया गया। उन्होंने जीतू पटवारी को रहली विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर अटल सेतु, निर्माणाधीन झूला पुल और अन्य परियोजनाओं को देखने का निमंत्रण भी दिया।

एफएसएल भर्ती का अंतिम परिणाम जारी, 97 अभ्यर्थियों का चयन

भोपाल, देशबन्धु। मध्य प्रदेश राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) के अराजपत्रित सेवा (गृह/पुलिस) विभाग के अंतर्गत प्रयोगशाला तकनीशियन, प्रयोगशाला सहायक और प्रयोगशाला परिचारक के पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई है। अंतिम चयन परिणाम 5 अगस्त को एमपी ऑनलाइन पर जारी कर दिया गया। कुल 97 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन किया गया है।

पांच माह में पूरी हुई भर्ती प्रक्रिया, तकनीशियन, सहायक और परिचारक पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ

शासन ने इन पदों पर भर्ती के लिए 13 जनवरी 2026 को स्वीकृति प्रदान की थी। इसके बाद 10 मार्च को भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया। भर्ती प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर तेजी से संचालित करते हुए महज पांच माह में अंतिम चयन सूची जारी कर दी गई।

चयन समिति द्वारा 14 और 15 जून को भोपाल के जहांगीराबाद स्थित शासकीय मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय में तीन पालियों में लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा और निर्धारित चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 5 अगस्त को अंतिम परिणाम घोषित किया गया।

अंतिम चयन सूची के अनुसार प्रयोगशाला तकनीशियन के 19, प्रयोगशाला सहायक के 28 और प्रयोगशाला परिचारक के 50 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। अभ्यर्थी अपना परिणाम एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर देख सकते हैं।

चयनित अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन, चिकित्सीय परीक्षण और अन्य आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद नियमानुसार नियुक्ति दी जाएगी। अभ्यर्थियों को आगामी सूचना के लिए एमपी ऑनलाइन और मध्य प्रदेश पुलिस की अधिकृत सूचनाओं पर नजर रखने की सलाह दी गई है।

प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचे आशुतोष तिवारी ने मीडिया से कहा-

दतिया उपचुनाव में नरोत्तम की भूमिका पर फैसला जांच समिति करेगी

भोपाल, देशबन्धु। दतिया उपचुनाव भाजपा प्रत्याशी रहे आशुतोष तिवारी ने कहा है कि पार्टी हार के कारणों की विस्तृत समीक्षा कर रही है। इस चुनाव में डॉ. नरोत्तम मिश्रा की भूमिका पर उन्होंने कहा इस पर अंतिम फैसला पार्टी की जांच समिति करेगी।

भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे आशुतोष तिवारी ने मीडिया से कहा कि पार्टी चुनाव में कांग्रेस की रणनीति को पूरी तरह समझ नहीं सकी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सुनियोजित तरीके से चुनाव लड़ा और भाजपा उसकी रणनीति को समय रहते नहीं भांप पाई। तिवारी ने कहा कि अगर अनजाने में पार्टी के कुछ लोग भी उस रणनीति का हिस्सा बने हैं तो उनकी भी पहचान की जाएगी। डॉ. मिश्रा की भूमिका पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि कौन कितना जिम्मेदार है, इसका फैसला भी जांच समिति ही करेगी। उन्होंने कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव की तुलना में हार का अंतर कम हुआ है। उन्होंने इसे सकारात्मक पक्ष बताते हुए कहा कि वह आगे भी क्षेत्र की सेवा करते रहेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वह खुद को पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता मानते हैं। पार्टी नेतृत्व जो भी जिम्मेदारी देगा, उसका पूरी निष्ठा से पालन करेंगे। उन्होंने दतिया भाजपा जिला अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चाओं पर कहा कि यह फैसला पूरी तरह पार्टी नेतृत्व का होता है।

डॉ. मिश्रा से सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात हुई

पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा से हाल ही में हुई मुलाकात को लेकर भी उन्होंने कहा कि यह केवल एक सामान्य शिष्टाचार मुलाकात थी। इसके कोई राजनीतिक मायने नहीं हैं और इसे किसी अन्य रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। डॉ. मिश्रा ने बुधवार को आशुतोष तिवारी से मुलाकात की थी।

उल्लेखनीय है कि दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,016 वोटों से हराया था। इसके बाद भाजपा ने चुनाव परिणाम की समीक्षा शुरू कर दी है, 2 सदस्यीय जांच समिति की सिफारिश पर प्रदेश भाजपाध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल ने दतिया जिला इकाई सहित जिले के सभी प्रकोष्ठों को भंग कर पदाधिकारियों को हटा दिया है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात की।

सरकार ने 'गोबरधन योजना' को दी मंजूरी

नई दिल्ली, देशबन्धु। सरकार देश में संपीड़ित बायोगैस को बढावा देने और इसे भविष्य के ऊर्जा स्रोतों का प्रमुख स्तंभ बनाने के लिए 23 हजार 731 करोड़ रूपये के कुल खर्च के साथ दस वर्ष के लिए गोबरधन योजना शुरू करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में बताया कि मंत्रिमंडल ने 23,731 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय पुर्नचक्रण जैव ऊर्जा , गोबरधन योजना को मंजूरी दे दी है। यह योजना कृषि अवशेष, पशु गोबर, चीनी मिलों के अपशिष्ट, नगर निकायों के जैविक कचरे और अन्य बायोमास संसाधनों को स्वच्छ ईंधन, जैविक खाद, ग्रामीण आय में बदलने के लिए शुरू की गई है।

मध्य प्रदेश से गुजरात तक फैला नशे का नेटवर्क, 2 दंपति गिरफ्तार

भोपाल/मंदसौर, एजेंसी। मध्य प्रदेश से गुजरात और राजस्थान तक नशे के कारोबार का नेटवर्क सामने आया है। मंदसौर पुलिस ने भोपाल के एक दंपति को 62 किलो से अधिक डोडा चूरा के साथ गिरफ्तार किया है, जबकि गुजरात की वडोदरा पुलिस ने मंदसौर निवासी दंपति को 1.396 किलो एमडी ड्रग्स के साथ पकड़ा है।

- मंदसौर में भोपाल के दंपति से 62 किलो डोडा चूरा बरामद
- वडोदरा में मंदसौर के दंपति के पास मिली 41 लाख की एमडी

अफजलपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कमालपुरा फंटा के पास घेराबंदी कर कादु उर्फ राधा बाई (48) और आशाराम उर्फ गंभीर (52) को गिरफ्तार किया। दोनों भोपाल के गांधी नगर क्षेत्र के निवासी बताए गए हैं। उनके पास से करीब सवा लाख रुपये कीमत का 62 किलो से अधिक डोडा चूरा बरामद हुआ। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी महिलाओं के स्व-सहायता समूह की आड़ में मादक पदार्थों की तस्करी करते थे। पुलिस से बचने के लिए वे दुधमुंहे बच्चों को भी साथ रखते थे।

इधर वडोदरा पुलिस ने अय्यूब खान और उसकी पत्नी नाजमीन को 1.396 किलो एमडी के साथ गिरफ्तार किया। जब्त ड्रग्स की कीमत करीब 41 लाख रुपये बताई गई है। पुलिस ने स्कॉर्पियो, मोबाइल सहित कुल 57.19 लाख रुपये का माल जब्त किया। पूछताछ में आरोपियों ने माल मंदसौर के एक तस्कर से लेने और अहमदाबाद के व्यक्ति को पहुंचाने की बात बताई है। दोनों मामलों में एनडीपीएस कानून के तहत प्रकरण दर्ज कर नेटवर्क की जांच की जा रही है।

दूरदर्शन मध्य प्रदेश ने शुरू की बुंदेली समाचार सेवा

बंदुेली भाषा में समाचार सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का प्रभावी माध्यम : डॉ. कुमार

भोपाल, देशबन्धु। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा है कि बुंदेली जैसी समृद्ध लोकभाषा में समाचार प्रसारण क्षेत्र के लोगों को उनकी अपनी बोली में विश्वसनीय समाचार उपलब्ध कराने के साथ-साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का प्रभावी माध्यम बनेगा। उन्होंने भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम को वीडियो संदेश द्वारा संबोधित करते हुए अपनी शुभकामनाएं दीं।

दूरदर्शन मध्य प्रदेश ने क्षेत्रीय बोलियों के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए पर आज समाचार एकांश बुंदेली समाचार का शुभारंभ किया गया। महानिदेशक, डीडी (न्यूज़) ममता वर्मा ने दूरदर्शन केंद्र, ने भोपाल में आयोजित समारोह में इस विशेष समाचार बुलेटिन की शुरुआत की गई। जिसमें अतिरिक्त महानिदेशक, डीडी न्यूज़ (पीबी-शब्द) ऋचु शुक्ला, निदेशक एवं क्षेत्रीय समाचार प्रमुख, डीडी न्यूज़ मध्य प्रदेश पूजा पी. वर्धन, वरिष्ठ बुंदेली साहित्यकार एवं पद्मश्री कैलाश मड़वैया सहित कई अधिकारी उपस्थित थे। महानिदेशक, (न्यूज़) ममता वर्मा ने कहा कि सार्वजनिक प्रसारक के रूप में प्रसार भारती भारतीय भाषाओं, बोलियों तथा सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण और संवर्धन के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। अतिरिक्त महानिदेशक, डीडी न्यूज़ (पीबी-शब्द) ऋचु शुक्ला ने कहा कि क्षेत्रीय बोलियों में समाचार प्रसारण से दर्शकों की सहभागिता बढ़ेगी तथा उनके साथ विश्वास का संबंध और अधिक सुदृढ़ होगा। निदेशक एवं क्षेत्रीय समाचार प्रमुख, डीडी न्यूज़ मध्य प्रदेश पूजा पी. वर्धन ने कहा कि बुंदेली समाचार डीडी न्यूज़ मध्य प्रदेश का पहला बोली आधारित समाचार बुलेटिन है, जो प्रतिदिन दोपहर 12 बजे आधे घंटे (30 मिनट) प्रसारित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह दूरदर्शन की भारत की समृद्ध भाषाई एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन की प्रतिबद्धता का एक ऐतिहासिक पड़ाव है।

लोकनृत्य, पारंपरिक संगीत और लोककलाओं ने बांधा समां, सांस्कृतिक एकता और वैश्विक सद्भाव का दिया संदेश

ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव में 6 देशों की विरासत का रंग

भोपाल, देशबन्धु। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता-2026 के अंतर्गत गुरुवार को रवींद्र भवन में ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव-2026 का आयोजन किया गया। संस्कृति मंत्रालय, केंद्र सरकार द्वारा आयोजित इस महोत्सव में छह देशों के कलाकारों ने अपनी पारंपरिक कला, संगीत और नृत्य के माध्यम से सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन किया। आयोजन ने देशों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान और आपसी सहयोग को नई मजबूती दी।

ब्रिक्स सांस्कृतिक कार्य समूह की तीसरी बैठक के दूसरे दिन आयोजित महोत्सव का आधार 'सर्वे भवन्तु सुखिन:' की भावना रही। इसके जरिए शांति, सद्भाव और सामूहिक कल्याण के भारत के सभ्यतागत दर्शन को प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता-2026 की थीम 'लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और निरंतरता के लिए निर्माण' के अनुरूप रहा। कार्यक्रम की शुरुआत प्रतिभागी देशों की सांस्कृतिक परेड से हुई। बेलारूस, ब्राजील, इंडोनेशिया, रूसी संघ, संयुक्त अरब

अमीरात और भारत के कलाकारों ने अपनी-अपनी सांस्कृतिक परंपराओं का प्रदर्शन किया।

बेलारूस के गेनाडी त्सितोविच राष्ट्रीय अकादमिक लोक कॉयर के कलाकारों ने पारंपरिक लोकगीतों और हास्य लोकनृत्यों से दर्शकों को आकर्षित किया। ब्राजील की एफ्रो-ब्राजीलियाई कला 'कैपोएरा' ने मार्शल आर्ट, नृत्य, संगीत और एक्रोबैटिक कौशल का अनूठा संगम प्रस्तुत किया।

इंडोनेशिया के कलाकारों ने बाली का पारंपरिक स्वागत नृत्य 'पुष्पांजलि' और प्रंबनन मंदिर से प्रेरित जावानीस नृत्य-नाटिका 'द लीजेंड ऑफ रोरो जोंगरांग' प्रस्तुत की। रूस के कलाकारों ने बालालाइका, बायान और डोमरा सहित पारंपरिक वाद्ययंत्रों पर मनमोहक संगीत प्रस्तुत किया। संयुक्त अरब अमीरात के संगीतकार सैफ अल-अली ने समकालीन प्रभावों के साथ अमीराती और अरब संगीत परंपराओं को मंच पर जीवंत किया। वहीं भारत की ओर से 'मारू रंग—राजस्थान की विरासत' कार्यक्रम में घूमर, चरी, कालबेलिया और भवाई जैसे लोकनृत्यों की प्रस्तुति हुई।

महोत्सव का समापन ग्रैंड फिनाले से हुआ, जिसमें सभी देशों के कलाकार एक मंच पर आए। इस दृश्य ने सांस्कृतिक विविधता में एकता, आपसी सम्मान और वैश्विक सद्भाव का संदेश दिया। आयोजन ने कला और संस्कृति के जरिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग तथा जन-जन के बीच संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया।

पत्रकार प्रकाशन प्रा.लि. के लिए गिरिराज चाचा द्वारा श्री सिद्धि विनायक प्रिंटर्स, प्लाट नं. 26 बी देशबन्धु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी. नगर, भोपाल म.प्र. 462011 से मुद्रित एवं प्रकाशित, संपादक: पलाश सुरजन, कार्यकारी संपादक: ज़ाकिर अली* फोन 0755-4222971, ई-मेल deshbandhubpl1@yahoo.co.in प्रेस पंजीयन-प.स. 45096/85 * समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार।

अब न देरी, न दूरी

मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान
अब सरकार हमारे द्वार

- नामांतरण, सीमांकन व फाइलें अब अटकेंगी नहीं, होगा ऑन-द-स्पॉट क्लीयरेंस!
- हर योग्य किसान को फार्मर ID और टॉप-क्वालिटी खाद-बीज की इंस्टेंट डिलीवरी
- आयुष्मान कार्ड का 100% कवरेज + हॉस्पिटल्स का ऑन-ग्राउंड सरप्राइज ऑडिट
- e-KYC और आधार कार्ड अपडेशन बिना किसी झंझट के तुरंत डन!
- कुटीर व लोकल बिजनेस को N.O.C. और स्वीकृतियों का सुपरफ़ास्ट अप्रूवल
- PM आवास, नल से जल, राशन और लॉ एंड ऑर्डर का स्ट्रिक्ट ऑन-स्पॉट चेक
- लोक सेवा गारंटी प्रकरणों का शत-प्रतिशत समाधान, सरकारी कार्यप्रणाली का इवैल्यूएशन और जनसमस्याओं का क्विक सॉल्यूशन
- आंगनवाड़ी सेवाओं व बच्चों के पोषण की निगरानी और स्कूल-कॉलेजों की शिक्षा का मूल्यांकन
- सड़क, तालाब, अमृत सरोवर और अन्य विकास कार्यों का भौतिक सत्यापन

शुभारंभ
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा
छिंदवाड़ा, मध्यप्रदेश

D-11073/26

सीधा प्रसारण @Cmmadhyapradesh @jansampark.madhyapradesh @Cmmadhypradesh @JansamparkMP JansamparkMP

मध्यप्रदेश जनसंपर्क द्वारा जारी

7 अगस्त 2026 से 8 जनवरी 2027
हर शुक्रवार, सरकार जनता के द्वार

सहयोग : मध्यप्रदेश माध्यम/2026

देशबन्धु

भोपाल, शुक्रवार, 7 अगस्त 2026

संस्थापक-संपादक : स्व. मायाराम सुरजन

कॉकरोच अब किस दिशा में बढ़ेंगे

जंतर-मंतर पर पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन खत्म हो चुका है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया है। इस बीच प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की ज्यादती को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिन पर सुनवाई चल रही है। इस तरह देखा जाए तो कॉकरोच जनता पार्टी ने मोदी सरकार के नुमाइंदों के साथ मिलकर जो समझौता किया था और महीने भर से ऊपर चला आंदोलन खत्म हुआ था, तो अब कॉकरोच जनता पार्टी किस दिशा में आगे बढ़ेगी। क्या वह किसी राजनैतिक दल में तब्दील होगी, या फिर शिक्षा व्यवस्था के जो अनसुलझे सवाल हैं, उन्हें उठाएगी, या उसकी भूमिका बस यहीं तक सीमित थी, ऐसे कई सवालों पर जवाब मिलने अब शुरु हो गए हैं।

बुधवार और गुरुवार दो दिनों तक कॉकरोच जनता पार्टी की बैठक चली और अब अभिजीत दिपके ने गुरुवार को अपने अगले कदम के बारे में बताया है। दिपके के मुताबिक सीजेपी अब देश भर में एक नयी मुहिम छेड़ रही है, जिसका नाम होगा 'क्या बोलती पब्लिक' इस मुहिम की घोषणा करते हुए दिपके ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं को समझना और उनके लिए काम करना होगा। बकौल, दिपके इस अभियान का सबसे पहला ध्यान शिक्षा क्षेत्र पर होगा, धीरे-धीरे इसे अन्य मुद्दों पर भी केंद्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा पर सबसे पहले ध्यान इसलिए दिया गया है क्योंकि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग की बढ़ती फीस की वजह से कई परिवार अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध नहीं करवा पाते। उन्होंने कहा, देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार हमारा पहला मुद्दा होगा। इस पर हमें काम करना है। हमारा मानना है कि देश में शिक्षा महंगी हो गई है। पहली कक्षा के लिए सालाना फीस 1 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए के बीच है। इसके अलावा कई जगह डोनेशन भी चलता है। दिपके ने सवाल उठाया कि देश में लोगों की आय इतनी कम है। आखिर वह कैसे अपने बच्चों को इतनी फीस देकर पढ़ा पाएंगे? कॉलेज और कोचिंगों की महंगी फीस कई परिवारों को कर्ज के जाल में फंसा रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कॉकरोच पार्टी छात्रों के और तमाम परिवारों के इस आर्थिक बोझ को कम करना चाहती है। अभिजीत दिपके ने भीम राव अंबेडकर का जिक्र करते हुए कहा कि शिक्षा पर सभी का अधिकार है। शिक्षा को सभी के लिए उपलब्ध होना चाहिए। लेकिन आज के समय में शिक्षा केवल एक मुनाफे का धंधा बन चुकी है।

अभिजीत दिपके की ये बातें भारतीय राजनीति के लिए देजा वू पल समान लग रही हैं। फ्रेंच भाषा से लिए गए इस शब्द का अर्थ है पहले से देखा या महसूस किया हुआ। ज्यादा नहीं बस डेढ़ दशक पहले 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी बनी थी। अरविंद केजरीवाल की बनाई यह पार्टी इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम के अभियान से ही निकली थी। आम आदमी पार्टी ने भी जनता पर पकड़ बनाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी जैसे बुनियादी मुद्दों पर ही जोर दिया। और इसमें कोई संदेह नहीं कि जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो चाहे सरकारी स्कूल हों या मोहल्ला क्लिनिक की अवधारणा इनसे लाखों लोगों की जिंदगी में सहूलियत बढ़ी। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बहुत हद तक आप सरकार ने सुधार किया था। फरवरी 2020 में जब ट्रंप भारत के दौरे पर थे, तो अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप ने एक सरकारी स्कूल का दौरा भी किया था।

आम आदमी पार्टी ने अपने गठन के वक्त यही दावा किया था कि वह राजनीति में बदलाव करेगी और मौजूदा चलन से हटकर काम करके दिखाएगी। लेकिन राजनैतिक मजबूरी कहें या महत्वाकांक्षा, आम आदमी पार्टी भी अब उसी रवैये पर चलती है जैसे बाकी राजनैतिक दल। भाजपा के विरोध में आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनना मंजूर किया और उसी कांग्रेस से हाथ मिलाया, जिसकी मुखालफत वो करती रही है। लेकिन अब उसे इस गठबंधन में सहजता महसूस नहीं हुई तो वह अलग भी हो गई है। भविष्य में आम आदमी पार्टी क्या अकेले ही रहेगी या फिर किसी गठबंधन का हिस्सा बनेगी यह कहना कठिन है।

ठीक ऐसे ही अब कॉकरोच जनता पार्टी का हाल भी दिख रहा है। 'क्या बोलती पब्लिक' में जिस पब्लिक पर जोर दिया जा रहा है, वह आम आदमी ही है। बेशक अभिजीत दिपके ने अभी कहा है कि वह राजनीतिक पार्टी नहीं बनेंगे। बल्कि स्थानीय स्तर पर सुधार करने के लिए एक 'प्रेशर ग्रुप' यानी दबाव बनाने वाले समूह की तरह काम करेंगे। और जनता के बीच जाकर जानेंगे कि लोग देश के मौजूदा हालात के बारे में क्या सोचते हैं और उन्हें किन मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बिना राजनैतिक आधार के क्या वे केवल प्रेशर ग्रुप बनाकर उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे, जिसके लिए, कॉकरोच जनता पार्टी बनी है। बेशक मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की टिप्पणी से आहत होकर उसके लिए दिए गए जवाबी तंज में कॉकरोच जनता पार्टी बनी है। लेकिन जंतर-मंतर पर पेपर लीक के विरोध में आंदोलन खड़ा करने में उसकी ही भूमिका रही है। बाद में वामदल के छात्र संगठन इस आंदोलन में शामिल हुए तो इसमें नए आयाम जुड़े और फिर लगभग विपक्ष के हर दल के नेता ने जंतर-मंतर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। यह आंदोलन सीजेपी तक शामिल नहीं रहा, लेकिन यह भी सच है कि आंदोलनकारियों की तरफ से सरकार से समझौता सीजेपी ने ही किया। ऐसे हालात में भले ही अभी सीजेपी राजनैतिक दल में तब्दील नहीं होगी। लेकिन वो उन्हीं मुद्दों को उठाने की बात कर रही है, जिनके समाधान लोकतांत्रिक राजनीति का हिस्सा बनकर ही तलाशा जा सकता है। अब सीजेपी क्या विपक्षी मोर्चे का अघोषित हिस्सा बनकर काम करेगी, क्या शिक्षा, बेरोजगारी, पेट्रोल में एथेनॉल की मिलावट जैसे मुद्दों के अलावा वह अपनी विचारधारा स्पष्टता के साथ जनता के सामने रख पाएगी, या वाकई सामाजिक आंदोलन की तरह ही काम करेगी और पूरी तरह राजनीति से अलग रहेगी, इन सारे सवालों के जवाब निकट भविष्य में मिल जाएंगे, ऐसी उम्मीद है।

भारत में बढ़ती असमानता और सिकुड़ते अवसर

■ राजेश पांडेय

भारत को हमेशा चमकीली संभावनाओं का देश माना जाता है। पुराने दौर में उसके लिए सोने की चिड़िया विशेषण का इस्तेमाल होता था। उसमें दुनिया की बड़ी ताकत के बतौर उभरने की क्षमता रही है। लेकिन वर्तमान स्थिति खोए हुए अवसरों की अनंत कथा के रूप में तब्दील हो गई है। पिछले कुछ वर्षों से देश में आर्थिक असमानता तेजी से बढ़ी है। राजनीतिक सत्ता के समान संपत्ति और साधन चंद लोगों के हाथों में सिमट गए हैं। नीतियों और प्राथमिकताओं में कुछ अमीरों को ज्यादा अहमियत मिल रही है। विश्व बैंक के आंकड़े और कई विशेषज्ञों के निष्कर्ष हालात की सही तस्वीर पेश करते हैं। जानकारी छिपाने और तोड़-मरोड़कर तथ्य पेश करने में माहिर सरकार भी कई बार सच बता देती है।

भारत ने आजादी के बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया था। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार का झुकाव समाजवाद और पूर्व सोवियत संघ की व्यवस्था की तरफ था। सरकार ने कई उद्योगों की बुनियाद रखी और बड़े बांध बनाए। विशुद्ध पूंजीवाद के पैरोकार कई अर्थशास्त्री देश की अपेक्षाकृत धीमी विकास दर के लिए इस मॉडल को जिम्मेदार मानते हैं। खासतौर से 2014 के बाद तो देश की तमाम समस्याओं का ठीकरा नेहरू के कार्यकाल पर फोड़ने का सिलसिला चल पड़ा है। बहरहाल, पं. नेहरू के दौर में बने एक विराट सार्वजनिक क्षेत्र ने बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा किए। कुछ नए शहर अस्तित्व में आए, अर्थव्यवस्था को सहारा मिला और अवसरों में आम लोगों की हिस्सेदारी बढ़ी थी। एक बेहद पिछड़े देश ने विकास की दौड़ में बड़े देशों से होड़ करने का सपना देखा था।

विकास के नेहरूवादी मॉडल में आगे जाकर कई सरकारों ने बदलाव किए हैं। लेकिन आर्थिक गैरबराबरी नए शिखर स्पर्श कर रही है। यहां हम आय, संपत्ति, उत्पादन के तुलनात्मक आंकड़ों से विकास की वास्तविक स्थिति का काफी हद तक मूल्यांकन कर सकते हैं। पेरिस इकानॉमिक्स स्कूल की विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 के मुताबिक भारत में कुछ लोगों के हाथ में संपत्ति और आय के जमा होने का स्तर चरम पर पहुंच गया है। वह दुनिया के सबसे ज्यादा असमान देशों की श्रेणी में आता है। राष्ट्रीय आय के 58 प्रतिशत हिस्से पर टॉप दस प्रतिशत लोगों का कब्जा है। दूसरी ओर सबसे निचली सीढ़ी पर बैठे 50 प्रतिशत लोगों के हिस्से में सिर्फ 15 प्रतिशत आमदनी आई है। कुल राष्ट्रीय आय के 40 प्रतिशत के मालिक एक फीसदी लोग हैं। विश्व बैंक की जुलाई 2026 में जारी एक रिपोर्ट में भारत को निम्न मध्यम आय की अर्थव्यवस्था बताया गया है। यह दर्जा 2009 से चल रहा है। मतलब पिछले 15-16 वर्षों से स्थिति लगभग यथावत है।

भारत के महाशक्ति बनने की संभावनाएं वर्षों से जताई जा रही हैं। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद तो विश्व गुरु, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था सहित कई दावे जोर-शोर से किए जा रहे हैं। लेकिन इन दावों पर संदेह बढ़ा है। इंडियन एक्सप्रेस में अभी हाल प्रकाशित सी राजामोहन के लेख में दो विशेषज्ञों के हवाले से कहा गया है कि भारत में बड़ी ताकत बनने की कई खूबियां हैं पर इतनी नहीं कि वह दुनिया की व्यवस्था को आकार दे सके। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के इतिहासकार ब्रेंडन सिम्स ने अपनी नई किताब- द रिटर्न ऑफ ग्रेट पावर्स में भारत को फ्रांस, जर्मनी और जापान के साथ महाशक्ति बनने की कगार पर खड़े देशों की सूची में रखा है। वे लिखते हैं यदि अगले दशक में भारत का कुल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) ब्रिटेन, जापान और जर्मनी से अधिक हो जाता है तब भी वह अमेरिका और चीन से बहुत पीछे तीसरे स्थान पर रहेगा। फॉरेन अफेयर्स पत्रिका में एक लेख में टफ्ट्स यूनिवर्सिटी के माइकेल बेकले की दलील है, विश्व राजनीति में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका तो बनी रहेगी लेकिन अपनी कई घरेलू कमजोरियों के कारण उसके वास्तविक महाशक्ति बनने की संभावना नहीं है।

भारत की आबादी में युवाओं की संख्या 29 से 30 फीसदी के बीच होने का अनुमान है। चीन सहित कई देशों की तरक्की के पीछे युवाओं की अहम भूमिका रही है। अब बुजुर्गों की संख्या बढ़ने से ऐसे देशों में काम करने वाली आबादी का प्रतिशत घटा है। उनकी अर्थव्यवस्था में गिरावट का एक कारण यह भी है। इस दृष्टि से भारत की बहुत अनुकूल स्थिति है।

ये घरेलू कमजोरियों कौन सी हैं? 2014 के बाद धार्मिक ध्रुवीकरण बढ़ा है, सरकारी एजेंसियों की कार्रवाई ने राजनीतिक दलों के साथ औद्योगिक, व्यावसायिक हलकों में डर पैदा किया है। उद्योगपति निवेश करने में हिचकिचा रहे हैं। केंद्र सरकार के मंत्री कभी चेतावनी तो कभी सवाल पूछने के अंदाज में कहते हैं, समझ में नहीं आता है उद्योगपति निवेश करने से पीछे क्यों हट रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में प्राइवेट सेक्टर का निवेश जीडीपी के 11 प्रतिशत पर आ गया है। वहीं मनमोहन सिंह के कार्यकाल में यह 14 प्रतिशत था। यह स्थिति उस वक्त है जब मोदी सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स की दर 2019 में 30प्रतिशत से घटाकर 22प्रतिशत कर दी।

अब उद्योगपति सरकार के फैसलों, उसकी नीतियों पर सवाल उठाने की बजाय उसकी तारीफ करने में लगे रहते हैं। हर बजट का जमकर स्वागत होता है। कुछ साल पहले तक उद्योगपति राहुल बजाज सरकार के खिलाफ खुलकर बोलते थे। फरवरी 2022 में उनके निधन के बाद उद्योग क्षेत्र से ऐसी कोई असरदार आवाज सामने नहीं आई है। कॉरपोरेट सेक्टर जोखिम भी नहीं उठा रहा है। उसका ध्यान किराए, ब्याज, शेयर बाजार के लाभांश और वायदा बाजार जैसी रेंटियर गतिविधियों पर ज्यादा है। 2012-13 से 2023-24 के आयकर रिटर्न के आंकड़ों का विश्लेषण बताता है, व्यावसायिक गतिविधियों से कंपनियों की कुल कर योग्य आय 57.3प्रतिशत से गिरकर 54.3प्रतिशत पर आ पहुंची थी।

न्यूयॉर्क के थिंक टैंक रोडियम ग्रुप और ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट का निष्कर्ष है, मैन्युफैक्चरिंग में भारत आगे नहीं बढ़ सका है। चीन की अर्थव्यवस्था में गिरावट और अमेरिका से व्यापार युद्ध ने दूसरे देशों के लिए आर्थिक फायदा उठाने के मौके बनाए हैं। लेकिन भारत के मुकाबले इस स्थिति को वियतनाम, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको जैसे देशों ने ज्यादा भुनाया है। पश्चिमी देशों की कई कंपनियों ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग चीन से हटाकर इन देशों में स्थानांतरित कर दी है।

निजी क्षेत्र के निवेश में गिरावट के बीच कुछ अमीरों की संपत्ति तेज रफ्तार से बढ़ रही है। दो उद्योगपतियों मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के बीच आगे निकलने की जबर्दस्त होड़ है। फोर्ब्स की सूची के अनुसार 2026 के मध्य में 8.84 लाख करोड़ रुपए की कुल संपत्ति के साथ अडानी भारत के सबसे अमीर शख्स थे। 2021 में उनकी संपत्ति 7.12 लाख करोड़ रुपए थी। उन्होंने पांच साल से कम समय में अपनी संपत्ति में ढाई लाख करोड़ रुपए का इजाफा कर लिया है। अडानी ने भारतीय अमीरों के सिंहासन पर लंबे समय से आसीन मुकेश अंबानी को पीछे हटा दिया है। 2021 में अंबानी की संपत्ति लगभग 8.84 लाख करोड़ रुपए थी। यह 2026 में घटकर 8.65 लाख करोड़ रुपए पर आ गई।

असमानता की एक और तस्वीर इन आंकड़ों में देखिए। बीते कुछ वर्षों में कुछ भारतीयों की आय और संपत्ति में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। अभी हाल में वित्त मंत्रालय ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक आय वाले लोगों की संख्या 2021-22 के 142 से बढ़कर 2025-26 में 576 हो गई थी। एक अरब 40 करोड़ की आबादी में यह संख्या मुट्ठी भर कही जाएगी। दूसरी और बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिन्हें अच्छा जीवन बिताने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार 2025 में नियमित कर्मचारियों का औसत सालाना वेतन 2.7 लाख रुपए (22 हजार 699 रुपए मासिक) था। वहीं आकस्मिक कामगार का औसत दैनिक वेतन सिर्फ 453 रुपए रहा।

पिछले माह जंतर-मंतर और कुछ राज्यों में युवाओं के आंदोलन का मुख्य कारण सिर्फ प्रश्नपत्रों का लीक होना नहीं है। उसने बढ़ती बेरोजगारी और सिकुड़ते अवसरों के खिलाफ अपनी चिंता, आक्रोश और असंतोष जताया है। हर साल गिनी-चुनी सरकारी नौकरियों में आवेदन करने वालों की संख्या लाखों में रहती है। अधिकतर युवाओं को उनकी योग्यता और क्षमता के हिसाब से रोजगार नहीं मिल रहे हैं। इसलिए वे मजबूरी में सामान की सप्लाई करने वाले रोजगार से काम चला रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में खाना और अन्य सामान की डिलीवरी करने वाली कंपनियों में रोजगार कई गुना बढ़ा है। शहरों में लोगों के दरवाजों पर गर्मागर्म खाना और सामान की डिलीवरी करने वाले लोगों में ज्यादातर युवा ही होते हैं।

भारत की आबादी में युवाओं की संख्या 29 से 30 फीसदी के बीच होने का अनुमान है। चीन सहित कई देशों की तरक्की के पीछे युवाओं की अहम भूमिका रही है। अब बुजुर्गों की संख्या बढ़ने से ऐसे देशों में काम करने वाली आबादी का प्रतिशत घटा है। उनकी अर्थव्यवस्था में गिरावट का एक कारण यह भी है। इस दृष्टि से भारत की बहुत अनुकूल स्थिति है। उसके सामने युवा आबादी से लाभ उठाने का मौका है। ऐसा सुनहरा अवसर एक शताब्दी में एक-दो बार ही मिलता है। इस बार चूके तो हम विकसित भारत का सपना साकार होते नहीं देख पाएंगे। अनंत संभावनाओं के बावजूद अमेरिका और चीन जैसे देशों के पीछे चलते रहेंगे।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।)

डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन : भारत की हरित क्रांति के जनक

भारत रत्न डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन को भारत में 'हरित क्रांति के जनक' के रूप में याद किया जाता है। कृषि विज्ञान के क्षेत्र में उनके दूरदर्शी एवं क्रांतिकारी योगदान ने भारत को खाद्यान्न संकट से उबारकर विश्व के सबसे बड़े अनाज उत्पादक देशों में शामिल कर दिया। वैज्ञानिक कार्यपद्धति, अभिनव प्रयोग, प्रभावी नीतिगत हस्तक्षेप तथा किसानों के साथ जमीनी स्तर पर जुड़ाव के माध्यम से उन्होंने भारतीय कृषि की दिशा और दशा दोनों बदल दी।

7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु में जन्मे डॉ. स्वामीनाथन ने अपना सम्पूर्ण जीवन खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा टिकाऊ (सस्टेनेबल) कृषि को बढ़ावा देने के लिए समर्पित किया। 1960 के दशक में जब भारत बार-बार अकाल, खाद्यान्न संकट और आयात पर निर्भरता जैसी गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा था, तब डॉ. स्वामीनाथन ने अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नेतृत्व से देश की कृषि व्यवस्था में ऐतिहासिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया।

डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन की कृषि विरासत के प्रमुख स्तंभ

1. उच्च उपज देने वाली किस्में:- डॉ. स्वामीनाथन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप उच्च उपज देने वाली गेहूं एवं धान की किस्मों का विकास और प्रसार था। उन्होंने नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग सहित अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों के साथ मिलकर मेक्सिको की कम ऊंचाई वाले गेहूं की किस्मों को भारत में लाने और उन्हें भारतीय किस्मों के साथ विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन नई किस्मों ने भारत की जलवायु एवं कृषि परिस्थितियों में बेहतरीन परिणाम दिए। इस हरित क्रांति की शुरुआत पंजाब और हरियाणा से हुई और शीघ्र ही पूरे देश में फैल गई।

प्रदीप पाटिल

जैविक खेती, सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप एवं स्प्रिंकलर), मृदा परीक्षण तथा जल संरक्षण को प्रोत्साहित करना तथा एवरग्रीन रिवोल्यूशन की अवधारणा को व्यवहार में उतारने के लिए किसानों को जलवायु-अनुकूल कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाना भी जरूरी है। सभी राज्यों एवं प्रमुख फसलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो।

2. आधुनिक कृषि अनुसंधान प्रणाली का निर्माण

डॉ. स्वामीनाथन ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) को एक सशक्त एवं गतिशील संस्था के रूप में विकसित किया, जिसने कालांतर में वैज्ञानिकों, किसानों और नीति-निर्माताओं के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके नेतृत्व में कृषि अनुसंधान केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित न रहकर किसानों की वास्तविक समस्याओं के समाधान पर केंद्रित हो गया।

3. टिकाऊ (सस्टेनेबल) कृषि के प्रबल समर्थक

डॉ. स्वामीनाथन अपने समय से बहुत आगे की सोच रखने वाले वैज्ञानिक थे। उन्होंने रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग तथा भूजल के अंधाधुंध दोहन से होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति समय रहते चेताया। उन्होंने 'सदाबहार क्रांति' (एवरग्रीन रिवोल्यूशन) की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसका उद्देश्य पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखते हुए कृषि उत्पादन में वृद्धि करना था। डॉ. स्वामीनाथन ने जैविक खेती, जल संरक्षण तथा फसल विविधीकरण को विशेष महत्व दिया।

4. छोटे एवं सीमांत किसानों के अधिकार तथा बीज-संप्रभुता

डॉ. स्वामीनाथन ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि आधुनिक विज्ञान का लाभ छोटे एवं सीमांत किसानों तक भी पहुंचे। उन्होंने किसानों के बीजों को सुरक्षित रखने, उपयोग करने और साझा करने के अधिकारों का पुरजोर समर्थन किया। उनके प्रयासों से पौधा-किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 अस्तित्व में आया, जिसे अभिनव प्रयोग और परंपरा के संतुलन का वैश्विक उदाहरण माना जाता है।

5. संवेदनशील एवं तथ्य-आधारित कृषि नीति के समर्थक

राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष के रूप में वर्ष 2006 में प्रस्तुत उनकी रिपोर्ट में अनुशंसा की गई कि फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) उत्पादन लागत से कम-से-कम 50 प्रतिशत अधिक होना चाहिए। किसानों को उचित मूल्य, ग्रामीण आधारभूत संरचना तथा संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने का उनका दृष्टिकोण आज भी भारत की कृषि नीति का महत्वपूर्ण आधार बना हुआ है।

भावी दिशा- आज भारत जलवायु परिवर्तन, बाजार की अनिश्चितता तथा जल संकट जैसी नई चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे समय में डॉ. स्वामीनाथन की सोच हमें आगे बढ़ने का स्पष्ट मार्ग दिखाती है। इसके लिए आईसीएआर जैसी संस्थाओं का आधुनिकीकरण तथा कृषि विस्तार सेवाओं को गांव-गांव तक पहुंचाया जाना जरूरी है ताकि प्रत्येक किसान नवीनतम अनुसंधान, तकनीक एवं कृषि सलाह से जुड़ सके। इसी प्रकार मोबाइल ऐप, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा डिजिटल कियोस्क जैसी आधुनिक और नवोन्मेषपूर्ण तकनीकों का व्यापक उपयोग लाभप्रद होगा।

जैविक खेती, सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप एवं स्प्रिंकलर), मृदा परीक्षण तथा जल संरक्षण को प्रोत्साहित करना तथा एवरग्रीन रिवोल्यूशन की अवधारणा को व्यवहार में उतारने के लिए किसानों को जलवायु-अनुकूल कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाना भी जरूरी है। सभी राज्यों एवं प्रमुख फसलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो। छोटे, सीमांत, बटाईदार, महिला एवं जनजातीय किसानों के लिए संस्थागत ऋण, फसल बीमा तथा बेहतर बाजार सुविधाओं तक पहुंच आसान बनाई जाए।

उनकी अन्य सिफारिशों जैसे ग्रामीण आधारभूत संरचना में निवेश तथा वर्षा आधारित कृषि के विकास हेतु राष्ट्रीय वर्षा आधारित क्षेत्र प्राधिकरण को लागू करना भी भारत की कृषि व्यवस्था को नई मजबूती प्रदान कर सकता है।

डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन का बड़प्पन उनके समग्र दृष्टिकोण में निहित है। उन्होंने आनुवंशिकी को नैतिकता से, उत्पादकता को पर्यावरण संरक्षण से तथा विज्ञान को मानवीय संवेदनाओं से जोड़ा। उनका विश्वास था कि कृषि केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि राष्ट्र की गरिमा, आत्मनिर्भरता और समृद्धि का आधार है। आज जब भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर है, तब डॉ. स्वामीनाथन के विचार और उनकी दूरदर्शिता पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक और प्रेरणादायक हैं।

ललित सुरजन की कलम से

दफा 499 और 500

वर्तमान समय के अधिकतर नेताओं का पढ़ने-लिखने से कोई वास्ता नहीं है। ऐसे में उनके पास अगर अपनी बात कहने के लिए सही शब्दों का अभाव है तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। दूसरे- किसी नेता का उसे सुनने आई भीड़ को देखकर प्रफुल्लित हो जाना स्वाभाविक है, लेकिन उससे कहीं अधिक वे टेलीविजन के कैमरों को देखकर पहले नकली आवेश में और फिर उसी रौ में बहते हुए अपने असली रूप याने एक कुपढ़ और बददिमाग व्यक्ति के रूप में सामने आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि अपने विरोधियों को जितना अधिक गरियाएंगे उनकी लोकप्रियता और वोटों में उतना ही इजाफा होगा। वे भूल जाते हैं कि आपका विरोधी ही आपके भाषणों का रिकार्डिंग करवा रहा है। तीसरे- नेताओं का अहंकार सिर पर चढ़कर बोलता है। इस दृष्टि से सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक जीवन में मर्यादा का पालन करने की नसीहत दी है तथा व्यक्ति की मानहानि को अपराध की श्रेणी में रखा है तो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए शायद उचित ही हुआ है।

(देशबन्धु में 19 मई 2016 को प्रकाशित)

https://lalitsurjan.blogspot.com/2016/05/499-500.html

प्रकाश पर्व

आठवें नानक हरिकृष्ण राय

हरिकृष्ण राय जी का इस धरा पर आगमन सातवें नानक हरि राय साहिब के गृहग्राम में 7 जुलाई को 1656 में हुआ था। उनकी माता का नाम कृष्ण कौर था। आप 6 अक्टूबर 1661 को गुरुगद्दी पर विराजमान हुए तब इनकी आयु मात्र सवा पांच साल की थी। इस तरह गुरु घर में छोटी उम्र हो बड़ी कोई मायने नहीं रखती। जहां तीसरे नानक गुरु अमरदास जी 73 वर्ष की आयु में गुरु गद्दी पर विराजमान हुए वहीं आठवें नानक मात्र मात्र पांच वर्ष की उम्र में गुरु गद्दी पर बैठे। क्योंकि शरीर तो बदलता रहा पर ज्योति वही दूसरे शरीर में प्रवेश करती रही-

जोत उही जगति उही, सा काया फेर पलटिये।

आप सातवें नानक हरि राय साहिब के छोटे सुपुत्र थे। उनके बड़े बेटे भाई राम राय जी थे जिन्हें बादशाह औरंगजेब के दिल्ली बुलाने पर यह कहकर गुरु पिता ने भेजा था कि गुरु घर की मर्यादा के अनुसार ही बादशाह के प्रश्नों का उत्तर देना और कोई करामात नहीं दिखाना। गुरु राम राय जी ने औरंगजेब के सभी प्रश्नों के जवाब गुरुघर के मर्यादा के अनुसार दिये लेकिन गुरुग्रंथ साहिब की गुरुवाणी की एक लाइन का जवाब बादशाह के बहकावे में आकर गलत जवाब दे दिया। गुरुवाणी के अनुसार लाईन थी- मिट्टी मुसलमान की पेड़े कुमिहार की पई के स्थान पर मिट्टी मुसलमान बेईमान की कहकर गुरुवाणी को तोड़-मरोड़कर पेश कर दिया। इससे बादशाह तो बहुत खुश हुए। उन्हें ईनाम के तौर पर दून की कुछ रियासतें जागीर के तौर पर दे दी। इस बात का पता लगा तो गुरुदेव हरिराय जी ने संदेशा भिजवा कि गुरुवाणी को तोड़-मरोड़ करने वाला अब गुरु घर में कभी नहीं आए और इस तरह गुरु गद्दी अपने छोटे बेटे हरिकृष्ण को सौंप दी।

पदासीन होने के बाद आप को भी बादशाह औरंगजेब ने दिल्ली बुलवाया पर पिता की आज्ञा का पालन करते हुए आपने दिल्ली जाकर नहीं मलेछ को दर्सन देहे के मुताबिक आपने दिल्ली जाने से इंकार कर दिया। बाद में राजा जयसिंह के घर साध संगत की आज्ञा अनुसार दिल्ली चल पड़े। रास्ते में पंखाजोर नामक गांव में एक लालचन्द्र नामक अहंकारी पंडित आपके पास आया और कहा कि आपको याद होगा कि गीता में श्रीकृष्णजी ने गीता उच्चारण की थी आप हरिकृष्ण हैं तो उसका अर्थ ही बता दीजिए। तब उसके अहंकार को तोड़ने के लिए आपने कहा कि आप गांव से किसी को भी ले आइये मैं उसका अर्थ उसके मुख से ही छड़ी रखकर दूंगा तो सब बता देगा। तब लालचंद्र ने एक गूंगे और बहरे छज्जू नामक युवक को ले आया। गुरुदेव ने उस गूंगे के सिर पर छड़ी रख दी और कहा कि लालचंद्रजी जिस जिस श्लोक का अर्थ पूछें आप उसका उत्तर देते जाइए इस तरह सारे श्लोकों का अर्थ बताते गया। उस दिन से ही वह गूंगा बोलने और सुनने लगा।

दिल्ली में आपके रहते ही चेचक की महामारी फैल गई तब आपने उसी बंगले में जहां आपने निवास किया था वहीं एक बावली का निर्माण कराया और कहा जो भी इस जल से स्नान करेगा उसका दुख-तकलीफ दूर हो जाएगा-

हरि हरि नाम दिओ दारु तिनि सगला रोग बिदारू।

वहीं सेवा करते हुए आप खुद भी चेचक के शिकार हो गए तब अपना अंतिम समय निकट जान गुरुघर की परंपरा के अनुसार पांच पैसे और एक नारियल रखकर शीश निवाते हुए कहा-बाबा बकाले और इस तरह गुरुतेग बहादुर नौंवे नानक के रूप में पदासीन हुए। आपका अंतिम संस्कार जमुना किनारे किया गया जहां आज गुरुद्वारा बाला साहिब और जिस बंगले में आपने निवास किया वहां गुरुद्वारा बंगला साहिब सुशोभित है।

इस तरह आप केवल तीन साल ही गुरुगद्दी पर रहे। इन तीन सालों में बहुत बड़े-बड़े कार्य किये। दशम गुरु ने फरमाया कि-

हरि कृष्ण धिआइये जिस डिठियां सब दुख जाये।

आज आपका प्रकाश पर्व है आपके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए आपके आदर्शों के अनुसार ही अपना जीवन मानव सेवा की भलाई में ही व्यतीत करें।

-इंदरसिंह आहुजा

आपके पत्र

सुविधा नहीं गरीब के जीवन का आधार है राशन व्यवस्था

भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। विकास, डिजिटलीकरण और कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा देशभर में होती है, लेकिन क्या यह योजनाएं देश के ग्रामीण क्षेत्रों में एक समान रूप से सभी को लाभान्वित करती हैं? इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। जबकि हकीकत यह है कि आज भी बिहार जैसे राज्यों के कई ऐसे ग्रामीण इलाके हैं, जहां हज़ारों गरीब परिवारों को राशन जैसी सुविधा समय पर नहीं मिल पाती है।

जिन घरों की आय इतनी कम है कि रोज़ कमा कर लाने से रोज़ का खाना बनता है, उनके लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि जीवन का आधार है। जब राशन समय पर नहीं मिलता, कम मात्रा में मिलता है या बिना किसी स्पष्ट कारण के राशन कार्ड से किसी सदस्य का नाम काट दिया जाता है, तब इसका सबसे बड़ा असर उन परिवारों पर पड़ता है जिनके लिए दो वक्त का भरपेट भोजन जुटाना भी किसी चुनौती से कम नहीं है।

बिहार के कई ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में ऐसे परिवार रहते हैं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करते हैं। खेतिहर मजदूर, दिहाड़ी श्रमिक, भूमिहीन किसान और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग अक्सर अनिश्चित आय पर निर्भर रहते हैं।

बरसात, बाढ़, सूखा या बीमारी जैसे हालात उनकी कमाई को और प्रभावित कर देते हैं। ऐसे समय में सरकारी राशन ही उनके घर का चूल्हा जलाए रखने का सबसे भरोसेमंद सहारा बनता है। यदि किसी महीने राशन मिलने में देरी हो जाए, तो परिवार को भूखे पेट सोने की नौबत तक आ जाती है।

एक आंकड़े के अनुसार बिहार में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लगभग 8.7 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। राज्य सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अनुसार, लगभग 2 करोड़ से अधिक राशन कार्ड राज्य में सक्रिय हैं, जिनके माध्यम से पात्र परिवारों को हर महीने प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न (चावल और गेहूं) अत्यंत रियायती दरों पर उपलब्ध कराया जाता है। वहीं अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के अंतर्गत आने वाले अत्यंत गरीब परिवारों को प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाता है। यही व्यवस्था लाखों परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है।

राशन कार्ड का महत्व केवल अनाज प्राप्त करने तक सीमित नहीं है। आज यह अनेक सरकारी योजनाओं तक पहुंच का महत्वपूर्ण दस्तावेज़ बन चुका है। पात्र परिवारों को राशन मिलने के साथ-साथ कई मामलों में आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ भी मिलता है। इसके अतिरिक्त कई सरकारी योजनाओं में पात्रता निर्धारित करने, पहचान प्रमाण के रूप में उपयोग करने तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने में भी राशन कार्ड महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

श्रुति कुमारी, मुजफ्फरपुर बिहार

सार-समाचार

सुनील शर्मा बने भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यकारिणी सदस्य

रायसेन, देशबन्धु। जिले के वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता एवं पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि एवं भाजपा खरबई मंडल के पूर्व प्रभारी सुनील शर्मा भारतीय जनता पार्टी रायसेन में जिला कार्यकारिणी सदस्य बनाए गए श्री शर्मा जी को कार्यकारिणी सदस्य बनाए जाने पर केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा सांची विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रभु राम चौधरी जी प्रदेश पदाधिकारी का आभार व्यक्त करते हुए उनके शुभचिंतकों ने बधाई दी

बारेलाल सूर्यवंशी को जिला कार्यकारिणी सदस्य की मिली जिम्मेदारी

रायसेन, देशबन्धु। जिले के वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं पत्रकार बारेलाल सूर्यवंशी को जिला कार्यकारिणी सदस्य की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा की अनुशंसा एवं प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की सहमति के अलावा सांसद एवं केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, तेज बहादुर सिंह संभाग प्रभारी, सुश्री राजो मालवीय जिला प्रभारी,पूर्व मंत्री एवं विधायक सांची डॉ. प्रभूराम चौधरी, पूर्व मंत्री रामपाल सिंह जी,स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल,पूर्व मंत्री एवं भोजपुर विधायक सुरेंद्र पटवा के अलावा मण्डल अध्यक्ष एवं प्रभारी जिला रायसेन के तथा जिले के वरिष्ठ जनों के विशेष सहयोग से यह जिम्मेदारी सौंपी गई है बताया जाता है कि बारेलाल सूर्यवंशी को जिला कार्यकारिणी सदस्य की जिम्मेदारी मिलते ही उनके द्वारा कहा गया कि जिस प्रकार से भाजपा पार्टी के द्वारा मुझको जो जिम्मेदारी सौंपी गई उस पर खरा उतरते हुए भाजपा पार्टी की नीतियों और रीतियों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करते हुए जो निर्देश भाजपा पार्टी से मिलेंगे उन निर्देशों का पालन करने से पीछे नहीं रहूंगा। बारेलाल सूर्यवंशी को जिला कार्यकारिणी सदस्य बनने पर उनके शुभचिंतकों के द्वारा बधाई और शुभकामनाऐं प्रदान की गईं।

सशक्त महिला का उजियारा अभियान का शुभारंभ

आष्टा, देशबन्धु। नगरपालिका परिसर स्थित सभाकक्ष में महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पादों और भारतीय मानकों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मानकों द्वारा सशक्त महिला का उजियारा अभियान का शुभारंभ किया गया। यह कार्यक्रम नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती हेमकुंवर रायसिंह मेवाड़ा के मुख्य आतिथ्य एवं नपा उपाध्यक्ष श्रीमती सिद्दीका बी, रिसोर्स पर्सन ब्यूरो ऑफ़ इंडियन स्टैंडर्ड्स दीपिका गायकवाड़ की विशेष उपस्थिति में संपन्न हुआ। आयोजित कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य महिलाओं तथा स्वयं सहायता समूहों की सदस्याओं को दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले सामानों की गुणवत्ता, सुरक्षा और भारतीय मानक संस्थान वाले प्रामाणिक उत्पादों के उपयोग के प्रति जागरूक करना है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रिसोर्स पर्सन ब्यूरो ऑफ़ इंडियन स्टैंडर्ड्स दीपिका गायकवाड़ ने बताया कि बाजार से सामान खरीदते समय आईएसआई मार्क और मानकों की जांच करना क्यों आवश्यक है। प्रामाणिक उत्पादों का चयन न केवल परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, बल्कि आर्थिक नुकसान और नकली सामानों से भी बचाता है। इस अवसर पर अनुराग, श्रीगणेश, बाबा रामदेव, राधिका, रानी, गोरी, सांवरिया, मोहिनी, कृष्णा, दुर्गा एवं इंदिरा स्वयं सहायता समूह की प्रतिनिधि रीना कुशवाहा, कौशल्या देवी, बबीता जायसवाल, गंगाबाई, नगीना, दुर्गाबाई, ममता, आशा शर्मा, नीता शर्मा, सोनू शर्मा, डाली, लता, मीना सेन, अरुण सोनी, संतोष परमार, नीलू ठाकुर, राजू बाई सहित सामुदायिक संगठक पार्वती शर्मा, शिवराजसिंह अहिरवार, नेहा मेवाड़ा, नरेन्द्र मालवीय एवं संदीप वर्मा आदि उपस्थित रहे।

एनएसयुआई ने की कार्रवाई की मांग

सातवीं के छात्र के साथ शिक्षक ने की बेरहमी से मारपीट

आष्टा, देशबन्धु। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन द्वारा सांदीपनी सीएम राइज स्कूल के प्राचार्य सितवत खान को अवगत कराते हुए प्रभारी प्राचार्य को ज्ञापन सौपा जिसमें शिक्षक विजय अडगाले द्वारा छात्र के साथ की गई मारपीट, जिससे छात्र के बेहोशी जैसी हालत बन चुके थे, सूचने मिलते ही भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष दीपक गोस्वामी पहूचे व उनके नेतृत्व में छात्र के पालक के साथ ज्ञापन सौपते हुए निश्पक्ष जांच कर शिक्षक पर कार्यवाही की मांग की। वही संगठन के छात्र नेता अंशु ठाकुर ने बताया कि विद्यालय शिक्षा का मंदिर है, जहाँ विद्यार्थियों को सुरक्षित एवं सम्मानजनक वातावरण मिलना चाहिए। किसी भी छात्र के साथ शारीरिक हिंसा या अमानवीय व्यवहार किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। एनएसयूआई ने स्कूल प्रशासन से मांग की है कि दोषी पाए जाने पर संबंधित शिक्षक के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाए, तथा विद्यार्थियों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित किया जाए। यदि समय रहते उचित कार्रवाई नहीं की गई, तो एनएसयूआई छात्रहित में लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। स्कूल कक्ष में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए उससे सत्यता की मोहर लगेगी। छात्र के साथ इस तरह से शिक्षक ने क्यों मारपीट की गई है यह बड़ा सवाल खड़ा करता है। बालक दिपेश पिता सुरज परमार निवासी मोरखेड़ी है। मारपीट के कारण छात्र भयभीत और डरा सहमा है, दिपेश की पिटाई के बाद अन्य विद्यार्थियों के भी डर का माहौल बना हुआ है। जबकि शासन ने सरकारी स्कूल में हर प्रकार की सुविधा छात्र हित में दी गई है ताकि गरीब से गरीब बच्चा चाहे दूरदराज रहता हो उसके लिए भी स्कूल बस की सुविधा देकर बेहतर शिक्षा के लिए उचित व्यवस्था की गई है लेकिन कुछ शिक्षक अपनी मनमानी कर शासन की मंशा पर पानी फैरते हुए छात्र के साथ मारपीट कर विद्यार्थियों में दहशत का माहौल बना रहें है। शिक्षक पर कार्यवाही को लेकर ज्ञापन देने वालों में जोगेन्द्र ठाकुर, हेमंत पवार, अमन भाटी, कौशल पटवारी, शुभम मालवीय, प्रतीक ठाकुर, राजकुमार आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

छात्र के साथ मारपीट करने वाले शिक्षक विजय अडगाले ने माफी नामा दिया है, इस तरह की दोबारा गल्ती नहीं होगी।

पटवारियों की चल रही हड़ताल, किसान हो रहे परेशान

ओबेदुल्लागंज, देशबन्धु। बजरंग तवर की खबर भोपाल हेडलाइंस (संवाददाता) नगर के तहसील टप्पा कार्यालय प्रांगण में मध्य प्रदेश पटवारी संघ की तहसील गोहरगंज शाखा के पटवारियों के द्वारा 3 अगस्त से हड़ताल चल रही है, तहसील शाखा के अध्यक्ष रामसिंह डावेल ने जानकारी देते हुए कहा कि पटवारियों की पांच सूत्रीय मांगों की मध्य प्रदेश शासन के द्वारा पूर्ती कराने के संबंध में चल रही है, श्री डावेल ने बताया कि हमारी पांच सूत्रीय मांगों में, केडर रिव्यू, प्रमोशन, समयमान-वेतनमान, विभागीय परीक्षा नायब तहसीलदार की, जज प्रोटेक्शन एक्ट, यह हमारी पांच मांगे हैं,, जब तक शासन के द्वारा हमारी मांगों की पूर्ति नहीं होगी जब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी, हड़ताल मंच पर आज अमृता श्रीवास्तव, सुनीता श्रीवास्तव, तहसील अध्यक्ष रामसिंह डावेल, प्रांतीय प्रवक्ता अथर हुसेन, राजकुमार, महेश वर्मा, नितिन व्यास, प्रदीप नागर, गौरव टंडन, गौरव राजुलकर, रविकांत द्विवेदी, राहुल तत्पाल, समुंन्दर सिंह आदि सहित पटवारीगण बड़ी संख्या में उपस्थित थे,, आपको बता दे की पटवारीयों की इस हड़ताल के कारण ग्रामीण क्षेत्र के कई किसान अपने काम कराने के लिए आते हैं और परेशान हो रहे है।

माँ द्वारका मेश्राम की स्मृति में शिक्षण सामग्री का वितरण किया

आष्टा, देशबन्धु। सहायक संचालक मंडी सचिव नरेंद्र मेश्राम की माँ श्रीमती द्वारका मेश्राम का निधन 6 जुलाई 2026 को हुआ था। आज उनके निधन को एक माह हो गया है। उनकी स्मृति में सांदीपनी शासकीय हायर सेकेंडरी की छात्र-छात्राओं की कक्षाओं में शिक्षण सामग्री का वितरण किया गए। सांदीपनी स्कूल के प्राचार्य सितवत खान, राजीव सारसिया, श्वेता पांडे एवं संजय जैन के मार्गदर्शन में किया। इस अवसर पर मंडी से नरेंद्र मेश्राम मंडी सचिव के साथ में अरविंद झवर, हरिनारायण पचलसिया, मनोज नागौरी, कुलदीप मेवाड़ा, रमेश चौरसिया, मांगीलाल विश्वकर्मा, सूरज मेवाड़ा उपस्थित थे। प्राचार्य ने श्री मेश्राम की प्रशंसा करते हुए कहा गया है कि ऐसे अमूल्य कार्य सभी को करना चाहिए एवं हमारे व्यवहार में लाना चाहिए।

ऐतिहासिक स्थल की बिजली व्यवस्था बदहाल, बार-बार कटौती से जनजीवन प्रभावित

मरम्मत के नाम पर लगातार बाधित हो रही आपूर्ति, जलापूर्ति भी हो रही ठप

सांची, देशबन्धु। विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक एवं पर्यटन नगरी सांची की बिजली व्यवस्था इन दिनों पूरी तरह चरमराई हुई नजर आ रही है। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल होने के कारण यहां निर्बाध विद्युत आपूर्ति बनाए रखने के लिए उच्च अधिकारियों द्वारा समय-समय पर विशेष निर्देश दिए जाते रहे हैं, लेकिन स्थिति में अपेक्षित सुधार दिखाई नहीं दे रहा है।

नगरवासियों का कहना है कि वर्षभर बिजली मरम्मत के नाम पर कार्य चलते रहते हैं, इसके बावजूद विद्युत आपूर्ति का कोई निश्चित समय नहीं रहता। बिजली कब चली जाए और कब वापस आए, इसका कोई भरोसा नहीं है। बार-बार होने वाली कटौती से आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

बिजली गुल होते ही पूरा नगर अंधेरे में डूब जाता है। इसके साथ ही पेयजल आपूर्ति भी पूरी तरह ठप पड़ जाती है, जिससे लोगों की दैनिक दिनचर्या प्रभावित होती है। नागरिकों का आरोप है कि पिछले लगभग पंद्रह दिनों से बिजली व्यवस्था सुधारने के नाम पर कटौती और अधिक बढ़ गई है।

इधर, सांची में जी-20 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के संभावित आगमन की चर्चाओं के बीच भी बिजली व्यवस्था का यह हाल स्थानीय लोगों में चिंता का विषय बना हुआ है। लोगों का कहना है कि संबंधित अधिकारी व्यवस्था सुधारने में अपेक्षित सफलता नहीं दिखा पा रहे हैं।

नगरवासियों ने यह भी शिकायत की है कि बार-बार बिजली गायब रहने के बावजूद बिजली बिलों में खपत लगातार दर्ज हो रही है, जिससे उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। नागरिकों ने विद्युत विभाग से शीघ्र स्थायी समाधान कर निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की है। विश्व धरोहर नगरी की पहचान के अनुरूप यदि मूलभूत सुविधाएं सुदृढ़ नहीं होंगी, तो स्थानीय नागरिकों के साथ-साथ यहां आने वाले पर्यटकों को भी असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा।

अब राज्य स्तरीय में जिले का प्रतिनिधित्व

सीहोर, देशबन्धु। नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के तहत आयोजित जिला स्तरीय युवा उत्सव के मुख्य समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत हुई समूह नृत्य प्रतियोगिता में संस्था की संचालिका डॉ. रूपाली सोनी के मार्गदर्शन में सरस्वती कथक डांस कला केंद्र के शास्त्रीय समूह नृत्य को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया।

समारोह के मुख्य अतिथि जिला जेल उप अधीक्षक दिलीप नायक सहित उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों द्वारा संस्था की संचालिका डॉ. रूपाली सोनी सहित संस्था की बालिकाओं को समूह नृत्य केटेगरी में *प्रथम पुरस्कार का मेडल एवं प्रशस्ति पत्र* देकर सम्मानित किया गया। अब संस्था की समूह नृत्य टीम अगले महीने भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय युवा उत्सव कार्यक्रम में सीहोर जिले का प्रतिनिधित्व करेगी। डॉ. रूपाली सोनी ने शहर में उत्कृष्ट कार्यक्रम करने एवं बच्चों को मंच उपलब्ध कराने के लिए आयोजन समिति का आभार व्यक्त किया। संस्था लगातार पिछले 6 वर्षों से शासन स्तर के विभिन्न कार्यक्रमों में प्रथम तीन में स्थान प्राप्त कर अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखा है। संस्था के इस नृत्य ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों सहित दर्शकों का मन मोह लिया और तालियों से गूंज उठा।

शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गौहरगंज में, उल्लास नवभारत

औबेदुल्लागंज, देशबन्धु। उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत विकासखंड औबेदुल्लागंज जिला रायसेन में,, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गौहरगंज में 400 छात्रों को प्रोजेक्ट वर्क के रुप में कार्य करने हेतु अक्षर साथी बन कर 4-4 असाक्षरों को चिन्हित कर हुक्क्षक्क पर पंजीयन करना होगा । उनकों पंजीयन कियें गये असाक्षरों कों अध्यापन कार्य करवाना है, परीक्षा में सम्मिलित करवाना है। उनकों कम से कम इतना तो पढ़ाना ही है कि, वें उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम की परीक्षा उत्तीर्ण कर सकें, तभी बेटियों को प्रोजेक्ट वर्क के नम्बर दिए जाएंगे। इस अवसर पर राधेश्याम नमचूरिया विकासखण्ड सह समन्वयक साक्षरता, परवचंद चौरे विकासखंड सहायक साक्षरता, अंकुश साहू संकुल सह समन्वयक साक्षरता, संस्था परिवार कें सभी शिक्षक/शिक्षिकाएं, संकुल प्राचार्य श्रीमती पदमावती राव उपस्थिति रही। संकुल प्राचार्य द्वारा सभी छात्राओं को समझया गया, कि प्रोजेक्ट वर्क के नम्बर तभी मिलेंगे, जब आप यह राष्ट्रीय कार्य कों पूरी लग्न, निष्ठा, मेहनत, ईमानदारी, एवं सेवा भाव केसाथ करेंगें। यदि किसी भी छात्रा को समस्या आती है तो वह सीधे संकुल प्राचार्य से सम्पर्क अवश्य करें। आपकी समस्या का समाधान तत्काल किया जायेगा। कार्यक्रम के अंत में सभी का आभार श्री प्रेमनारायण कीर कें द्वारा व्यक्त कर, कार्यक्रम का समापन किया गया।

कुत्तों के आंतक से बुजुर्ग बच्चों में दहशत, फिर एक व्यक्ति को काटा

आष्टा, देशबन्धु। शहर में लगातार बड़ती कुत्तों की आबादी का आलम यह है कि गली चौराहा मोहल्ला ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर कुत्तों का झुण्ड न हो। शहर की प्रत्येक जगह पर कुत्तों का आतंक होने के कारण अब छोटे छोटे बच्चो व बुजुर्गो का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। लगातार कुत्तों के काटने की घटना बड़ती जा रही है। विगत दिनों एक बालिका को घेरकर काट लिया था, वह तो गनीमत रही लोगों ने समय रहते बचा लिया नही तो बड़ी घटना हो सकती थी। एक बार फिर बुजूर्ग को कुत्ते ने उस समय काट लिया जब वह किसी काम के लिए कही जा रहे थे। शहर में दिनों दिन आवारा कुत्तों के काटने की घटनाएं बढ़ती जा रही है सबसे ज्यादा बुजुर्ग और बच्चे असुरक्षित है, जहां बुजुर्ग पर लगातार कुत्ते काटने की घटना बढ़ती जा रही तो वही स्कूल जाने वाले छात्र-छात्राओं को भी कुत्ते काट रहे हैं। इस मामले में अभी तक नगर पालिका ने कोई भी अभियान नहीं चलाया जिसके चलते शहरवासी असुरक्षित मान रहे हैं। शहर में कुत्तों की संख्या बढ़ती जा रही है इसके चलते अब हर किसी को आने-जाने वालों को कुत्ते काट रहे है। आज भी किला स्थित जैन मंदिर में जाने वाले बुजुर्ग को 10 से 12 कुत्तों ने घेर लिया और एक आवारा कुत्ते ने काट लिया। कुत्ते काटने की घटनाएं तेजी के साथ बड़ती ही जा रही है।

ग्रामीण क्षेत्र हो या शहर औसतम हर रोज दो से तीन मामले कुत्ते काटने के अस्पतालों में आ रहे हैं। कुत्ते काटने की घटनाएं सबसे ज्यादा साई कॉलोनी, बसस्टैंड, आवास कॉलोनी, बुधवारा, परदेसीपुरा, बड़ा बाजार, इंदिरा कॉलोनी, कन्नौद रोड, अलीपुर और किला क्षेत्र में सर्वाधिक आवारा कुत्तों के कारण नागरिक परेशान है आए दिन इन मोहल्ले में आने-जाने वाले लोगों को कुत्ते काट लेते हैं। मंदिर दर्शन के लिए जा रहे विमल जैन ने बताया कि जैसे ही वह मंदिर गेट के पास पहूंचे तभी कुत्तों ने घेर लिया और मुझे काट लिया। आज हालात यह है कि नगर में प्रत्येक दर्जनों कुत्तों का झुण्ड आसानी से देखा जा सकता है। बच्चे, बड़े एवं वाहन चालकों पर तेजी से दौड़ते हुए भोकते है। वाहन चालक इन से बचने के लिए दुर्घटनाग्रस्त भी हो चुके है। विगत दिनों नगर पालिका द्वारा एक दिन कुत्ते पकड़ने का अभियान चलाकर इतिश्री कर ली।

कुत्ते, सांड, आवारा पशुओं ने घेरा शहरः शहर में सैकड़ों कुत्ते जिनमें से अधिकांश खुजैले एवं हड़कियाए हो चुके हैं। जो लगातार लोगों को काट रहे हैं उसके बाद भी प्रशासन कोई ठोस अभियान नहीं चला पा रहा है। इसी प्रकार आवारा सांडों की बड़ती तादाद के कारण लोंगों को रास्ता बदल कर निकलना पड़ रहा है। अधिकांश चौराहों पर सांड खड़े रहते है। यहीं नहीं सांडों का आपस में विवाद होना भी आम बात हो चुकी है। साथ में पशुपालक अपने पालतु पशु को दुध निकालकर फिर शहर में छोड़ देते है। ग्रामीण क्षेत्रों से भी बड़ी तादाद में भी गायों का झुण्ड लगातार आ रहा है। जिसके चलते तेजी के साथ आवारा पशुओं की आबादी बड़ती हुई दिख रही है। विगत दिनों नगर पालिका ने गायों को पकड़कर गौशाला छोड़ी गई थी पर उसके बाद भी आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से किसान फसल को बचाने के लिए गायों को शहर की ओर हांक रहें है।

पर्यावरण संतुलन के लिए पौधारोपण आवश्यक : मेवाड़ा

आष्टा, देशबन्धु। नगरपालिका द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं शहर में हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अमृत हरित महाअभियान की शुरुआत की गई। अभियान के तहत पुराना इंदौर-भोपाल राजमार्ग पर स्थित नवनिर्मित नगरपालिका कार्यालय भवन परिसर में सघन पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इस महाअभियान का शुभारंभ नपाध्यक्ष श्रीमती हेमकुंवर मेवाड़ा, नपाध्यक्ष प्रतिनिधि रायसिंह मेवाड़ा एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी विनोदकुमार प्रजापति द्वारा पौधे लगाकर किया गया। कार्यक्रम के दौरान परिसर में छायादार एवं फलदार पौधे रोपे गए और उनके संरक्षण का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नपाध्यक्ष प्रतिनिधि रायसिंह मेवाड़ा ने कहा कि वृक्ष हमारे जीवन का आधार हैं और स्वच्छ पर्यावरण के बिना समृद्ध समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। बढ़ते तापमान और प्रदूषण के इस दौर में पौधारोपण ही आने वाली पीढ़ी के लिए सबसे बड़ा उपहार है। नगरपालिका का लक्ष्य केवल पौधे लगाना ही नहीं, बल्कि उनकी पूर्ण सुरक्षा और देखभाल सुनिश्चित करना भी है। शहर को हरा-भरा और सुंदर बनाने के लिए प्रत्येक नागरिक को इस अभियान से जुड़कर कम से कम एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। मुख्य नगरपालिका अधिकारी विनोदकुमार प्रजापति ने जानकारी देते हुए बताया कि अनुबंधित एजेंसी इन्नोवेशन एंड टेक्नोलॉजी इंटरप्राइजेज द्वारा नगरपालिका के नवनिर्मित भवन परिसर में लगभग 500 फलदार पौधों का रोपण किया गया है। संबंधित कंपनी ने ही पौधों की देखरेख और संधारण का कार्य करेगी। श्री प्रजापति ने यह भी कहा कि नगर में सार्वजनिक स्थलों को चिन्हित कर और भी फलदार पौधों का रोपण किया जाएगा। नवनिर्मित परिसर में रोपे गए सभी पौधों की नियमित सिंचाई और सुरक्षा के लिए परिसर में तार फेंसिंग की गई है, ताकि ये पौधे पल्लवित होकर परिसर को हरा-भरा बना सकें। पर्यावरण संवर्धन के लिए नगरपालिका आगे भी ऐसे अभियान निरंतर चलाती रहेगी।

इस अवसर पर नपाध्यक्ष हेमकुंवर मेवाड़ा, नपाध्यक्ष प्रतिनिधि रायसिंह मेवाड़ा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी विनोदकुमार प्रजापति, पार्षदगण डॉ. सलीम खान, अरशद अली, तारा कटारिया, उपयंत्री दीपक यादव, गबू सोनी, रमेश यादव, शीना खान, विनयकुमार, राजकुमार अकेला, लखन प्रजापति, संजू नाथ आदि मौजूद थे।

जनपद मुख्यालय से महज तीन किमी दूर विकास दावों की खुली पोल

ग्राम पंचायत उचेर अव्यवस्थाओं के घेरे में, दलदल बनी सड़कें, लोग हो रहे परेशान

__सांची, देशबन्धु।__ जनपद पंचायत सांची के अंतर्गत आने वाली 83 ग्राम पंचायतों में विकास के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन इन दावों की वास्तविकता ग्राम पंचायत उचेर के मुख्यालय में साफ दिखाई देती है। यहां वर्षों से पानी निकासी और नालियों की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण सड़कों पर जलभराव और दलदल की स्थिति बनी हुई है। ग्रामीणों को प्रतिदिन इसी गंदे और कीचड़ युक्त रास्ते से होकर आवागमन करना पड़ रहा है।

जानकारी के अनुसार ग्राम उचेर स्वयं ग्राम पंचायत उचेर का मुख्यालय है, जहां लगभग तीन हजार की आबादी निवास करती है। इस पंचायत के अंतर्गत चार गांव आते हैं, लेकिन पंचायत मुख्यालय की ही बदहाल स्थिति विकास कार्यों पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। ग्रामीणों का कहना है कि हल्की बारिश में भी सड़कें दलदल में तब्दील हो जाती हैं, जबकि कई स्थानों पर बिना बारिश के भी पानी भरा रहता है।

हैरानी की बात यह है कि ग्राम पंचायत उचेर, जनपद पंचायत सांची मुख्यालय से मात्र तीन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके बावजूद वर्षों से चली आ रही इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार पंचायत को समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन आज तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। पंचायत क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले जनपद पंचायत सदस्य भी इसी समस्या से प्रभावित हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब जनपद मुख्यालय के इतने निकट स्थित पंचायत की यह स्थिति है, तो दूरस्थ ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों की स्थिति का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है।

इनका कहना है

कैलाश बुनकर, जनपद पंचायत सदस्य, उचेर ने कहा, 'यह ग्राम पंचायत उचेर का मुख्यालय है। यहां सड़कों पर जलभराव आम बात हो गई है, जबकि अभी अधिक बारिश भी नहीं हुई है। हमने कई बार ग्राम पंचायत को इस समस्या से अवगत कराया, लेकिन समाधान नहीं निकला। अब हम जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) को पत्र देकर स्थायी समाधान की मांग करेंगे।'

आकांक्षा अग्रवाल, उपयंत्री, जनपद पंचायत सांची ने बताया, 'जिस सड़क पर अधिक जलभराव हो रहा है वह लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की सड़क है, इसलिए उसकी खुदाई पंचायत नहीं करा सकती। हालांकि गांव के भीतरी क्षेत्रों में जहां जलभराव की समस्या है, वहां निरीक्षण कर स्थायी समाधान के प्रयास किए जाएंगे।'

__आखिर कार अब प्रशासन इस समस्या को कितनी गंभीरता से लेता है :__ जनपद मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर स्थित उचेर पंचायत की बदहाल तस्वीर ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े कर रही है। अब ग्रामीणों को प्रशासन की ठोस कार्रवाई का इंतजार है।

सार समाचार

इकरा पब्लिक स्कूल में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित

सिरोंज, देशबन्धु। तहसील विधिक सेवा समिति, सिरोंज द्वारा बुधवार को इक्रा पब्लिक स्कूल में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में तहसील विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष एवं अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार पाण्डेय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने विद्यार्थियों को संविधान, विधिक अधिकारों एवं कर्तव्यों, न्याय व्यवस्था तथा कानून के महत्व की जानकारी देते हुए जागरूक, अनुशासित और जिम्मेदार नागरिक बनने का संदेश दिया। उन्होंने शिक्षा, नैतिक मूल्यों और निरंतर प्रयास के माध्यम से जीवन में सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा दी तथा न्यायिक सेवाओं सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और करियर के अवसरों पर भी उपयोगी मार्गदर्शन प्रदान किया। शिविर में पैरालीगल वालंटियर अहद पठान ने राष्ट्रीय एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित निःशुल्क विधिक सहायता, लोक अदालत, मध्यस्थता तथा अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों से आवश्यकता पड़ने पर इन विधिक सेवाओं का लाभ लेने का आह्वान किया। कार्यक्रम में विद्यालय के प्राचार्य, शिक्षकगण एवं अन्य गणमान्यजन उपस्थित रहे। विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए विधिक विषयों से जुड़े विभिन्न प्रश्न पूछे, जिनका विशेषज्ञों ने समाधान किया। शिविर का उद्देश्य विद्यार्थियों में कानून के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा विधिक अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सम्मान की भावना विकसित करना रहा।

सांदीपनि विद्यालय में सर्पदंश एवं आपदा प्रबंधन पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

सिरोंज, देशबन्धु। सांदीपनि विद्यालय में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं होमगार्ड विभाग के सहयोग से सर्पदंश एवं आपदा प्रबंधन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को जहरीले और विषहीन सांपों की पहचान, सर्पदंश होने पर प्राथमिक उपचार, क्या करें और क्या न करें तथा समय पर अस्पताल पहुंचने के महत्व की जानकारी दी गई। साथ ही जागरूकता पुस्तिकाएं वितरित कर अंधविश्वास छोड़ वैज्ञानिक उपचार अपनाने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में आग लगने और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान बचाव के व्यावहारिक उपाय भी बताए गए। बिना लाइफ जैकेट प्लास्टिक की बोतलों की सहायता से अस्थायी तैराकी उपकरण तैयार करने का प्रदर्शन किया गया तथा सीपीआर के माध्यम से आपात स्थिति में जीवन बचाने की प्रक्रिया समझाई गई। विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को आपदा के समय सतर्कता, सही निर्णय और त्वरित बचाव के महत्व से अवगत कराते हुए स्वयं सुरक्षित रहने और दूसरों की सहायता के लिए प्रेरित किया।यदि चाहें तो इसे दैनिक भास्कर या पत्रिका शैली में और अधिक संक्षिप्त भी किया जा सकता है।

इमरान प्रतापगढ़ी का जन्मदिवस, गरीबों को भोजन कर मनाया

सिरोंज, देशबन्धु। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के जन्मदिवस पर ब्लॉक कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग सिरोंज द्वारा सहयोग संस्था में गरीब, असहाय एवं जरूरतमंद लोगों को भोजन कराकर सेवा कार्य किया गया। कार्यक्रम का आयोजन ब्लॉक अल्पसंख्यक विभाग अध्यक्ष जुनेद खान के नेतृत्व में हुआ। वरिष्ठ कांग्रेस नेता केसर खान ने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति की सेवा ही सच्ची मानव सेवा है। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस सचिव विनोद सेन, जिला कांग्रेस सचिव सादिक कुरैशी, ओसफ हुसैन, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुरेश यादव, नगर कांग्रेस अध्यक्ष सेफू, पूर्व पार्षद भय्यंन भाई, पार्षद रामदयाल विश्वकर्मा सहित कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी ने इमरान प्रतापगढ़ी के उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना की।

एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत उमा यश अकादमी में हुआ पौधारोपण

गंजबासौदा, देशबन्धु। स्थानीय उमा यश अकादमी स्कूल में गुरुवार को 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के अंतर्गत भव्य पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो रहे। उन्होंने विद्यालय परिसर में पौधारोपण कर अभियान को गति प्रदान करते हुए विद्यार्थियों एवं नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान किया। विद्यालय पहुंचने पर नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों ने तिलक लगाकर एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर मुख्य अतिथि का आत्मीय स्वागत किया। इसके बाद विद्यालय के डायरेक्टर ब्रजेश रघुवंशी एवं प्राचार्या श्रीमती पूजा दांगी ने स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान किया। कार्यक्रम में शहर थाना निरीक्षक संजय वैदिया, यूथ आइकन अभिषेक सुमन, अंशुल पाराशर एवं अनुभव कटारे विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अपने संबोधन में प्रियंक कानूनगो ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति यदि अपने जीवन में कम से कम एक पौधा लगाकर उसकी नियमित देखभाल करे, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण सुनिश्चित किया जा सकता है।

समीक्षा बैठक में सामने आए लंबित प्रकरणों का निराकरण, विशेष प्रकरण मानकर दी गई स्वीकृति

कलेक्टर की पहल से 726 बालिकाओं को मिला लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ

विदिशा, देशबन्धु। विदिशा जिले में बालिकाओं के शिक्षा, सशक्तिकरण एवं सुरक्षित भविष्य को सुनिश्चित करने की दिशा में कलेक्टर अंशुल गुप्ता के मार्गदर्शन में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। लाड़ली लक्ष्मी योजना की समीक्षा बैठक के दौरान यह पाया गया कि पूर्व वर्षों के अनेक पात्र प्रकरण विभिन्न कारणों से स्वीकृत नहीं हो पाए थे। कलेक्टर गुप्ता ने इस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए ऐसे लंबित प्रकरणों की विशेष समीक्षा कराई और 1 वर्ष से 13 वर्ष तक की 726 पात्र बालिकाओं के प्रकरणों को विशेष प्रकरण मानते हुए स्वीकृति प्रदान की।

इस निर्णय से अब ये सभी बालिकाएं शासन की महत्वाकांक्षी लाड़ली लक्ष्मी योजना के समस्त लाभ प्राप्त कर सकेंगी। स्वीकृत बालिकाओं को 1.43 लाख का आश्वासन प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा।

योजना के प्रावधानों के अनुसार बालिकाओं को कक्षा 6वीं में प्रवेश पर 2,000, कक्षा 9वीं में 4,000, कक्षा 11वीं में 6,000 तथा कक्षा 12वीं में 6,000 की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से कॉलेज के प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने पर 12,500 रू. तथा स्नातक के अंतिम वर्ष में प्रवेश पर पुनः 12,500 रू. की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, जब बालिका 21 वर्ष की आयु पूर्ण करेगी, निर्धारित आयु से पूर्व विवाह नहीं करेगी तथा कक्षा 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित होने की निर्धारित शर्त पूरी करेगी, तब उसे 1,00,000 (एक लाख रुपये) की अंतिम प्रोत्साहन राशि सीधे उसके बैंक खाते में अंतरित की जाएगी।

कलेक्टर ने कहा कि शासन की मंशा है कि जिले की कोई भी पात्र बालिका योजना के लाभ से वंचित न रहे। समीक्षा बैठक में सामने आए लंबित प्रकरणों का निराकरण कर 726 पात्र बालिकाओं को योजना में शामिल किया गया है। यह निर्णय बालिकाओं की शिक्षा, आर्थिक सुरक्षा, आत्मनिर्भरता एवं सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रशासन भविष्य में भी यह सुनिश्चित करेगा कि जिले की प्रत्येक पात्र बालिका को समय पर योजना का लाभ मिल सके।

नाबालिग अपहरण मामले का फरार आरोपी गिरफ्तार

सिरोंज, देशबन्धु। थाना दीपनाखेड़ा पुलिस ने नाबालिग बालिका के अपहरण एवं पॉक्सो प्रकरण में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है।

पुलिस के अनुसार 28 जुलाई 2026 की रात नाबालिग बालिका के परिजनों ने थाना दीपनाखेड़ा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अज्ञात व्यक्ति उनकी पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। शिकायत के आधार पर अपराध क्रमांक 105/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। विवेचना के दौरान पीड़िता के कथनों एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर धारा 64(1) बीएनएस तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 3/4 भी प्रकरण में जोड़ी गई।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका तिवारी तथा एसडीओपी सोनू डाबर के मार्गदर्शन में विशेष टीम गठित की गई। टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर तंत्र की सहायता से पहले नाबालिग बालिका को सिरोंज क्षेत्र से सुरक्षित दस्तयाब कर परिजनों के सुपुर्द किया था।

इसके बाद लगातार फरार चल रहे आरोपी सूरज उर्फ भूरा (29 वर्ष), निवासी ग्राम नारायणपुर, थाना सिरोंज को पुलिस ने 5 अगस्त 2026 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी उपनिरीक्षक के.के. पवार, उपनिरीक्षक लालबहादुर सिंह, प्रधान आरक्षक दयाराम, प्रधान आरक्षक दीपक सेंगर, आरक्षक अमित खेमरिया, आरक्षक देवेंद्र एवं आरक्षक राजू प्रजापति की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

बिना लाइसेंस मांस बिक्री पर भी कार्रवाई, अतिक्रमण हटाया गया

तात्या टोपे बस स्टैंड पर नगर पालिका का छापा, 12 दुकानदारों के चालान

सिरोंज, देशबन्धु। नगर पालिका परिषद ने बुधवार को तात्या टोपे बस स्टैंड क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता को लेकर औचक निरीक्षण अभियान चलाया। मुख्य नगर पालिका अधिकारी रामप्रकाश साहू और स्वास्थ्य अधिकारी मनीष कुमार के नेतृत्व में नाश्ता एवं मिठाई की दुकानों सहित बस स्टैंड परिसर का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 12 दुकानदारों के चालान बनाए गए तथा बस स्टैंड क्षेत्र से अतिक्रमण भी हटाया गया। अधिकारियों ने दुकानदारों को प्रिंटेड कागज में खाद्य सामग्री परोसने पर रोक लगाते हुए केवल फूड-ग्रेड सिल्वर-कोटेड पेपर का उपयोग करने के निर्देश दिए। साथ ही दुकान और आसपास स्वच्छता बनाए रखने तथा गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री बेचने की हिदायत दी गई। कार्रवाई के दौरान बिना लाइसेंस संचालित दो मांस विक्रेताओं के विरुद्ध भी कार्रवाई कर आवश्यक लाइसेंस मिलने तक दुकानें बंद रखने के निर्देश दिए गए।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी रामप्रकाश साहू ने कहा कि नागरिकों के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

प्राचार्य द्वारा स्टाफ के अन्य शिक्षकों को दायित्व नहीं सौंपे गये

पीएम श्री स्कूल का वीईओ ने किया औचक निरीक्षण, मिली अनियमितताएं

सिरोंज, देशबन्धु। बुधवार को विकासखंड शिक्षा अधिकारी प्रतीक मेहरा द्वारा शासकीय हाई स्कूल पीएम श्री बरेज का औचक निरीक्षण किया गया निरीक्षण में कई अनियमितताएं पाई गई। मिली जानकारी अनुसार शाला में मध्यान्ह भोजन मेनू अनुसार नहीं पाया गया,जबकि प्राचार्य मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था स्वयं देखते हैं विद्यालय के शौचालयों की साफ सफाई नहीं होने के कारण शौचालय में गंदगी पायी गयी शौचालय में पानी की व्यवस्था भी उपलब्ध नहीं पायी गयी प्राचार्य द्वारा स्टाफ के अन्य शिक्षकों को दायित्व नहीं सौंपे गये शाला का लेखा रिकार्ड नहीं पाया गया भोजन करने वाले छात्र 65 मिले जिन्होंने भोजन किया छात्रों की उपस्थिति बहुत कम पायी गयी शाला में छात्र छात्राओं की उपस्थिति भी संतोषजनक नहीं पायी गयी विद्यालय में कक्षा एक से आठवीं तक के 152 बच्चे दर्ज हैं लेकिन विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा जांच करने पर 73 बच्चे ही उपस्थित पाए गए एवं हाई स्कूल के छात्र-छात्राओं की संख्या 169 है जिनमें से कुल 45 बच्चे ही उपस्थित पाए गए वी ई ओ ने प्राचार्य को निर्देशित किया की जो कमियां पायी गयीं है उनकी पूर्ति करें रिकार्ड सहित कार्यालय में उपस्थित हों

इनका कहना है-

निरीक्षण में अनियमितताएं मिली हैं कारण बताओ नोटिस जारी करेंगे

-प्रतीक मेहरा बीईओ सिरोंज

फसलों को मिला जीवनदान, कीट प्रकोप से मिलेगी राहत

मानसून की जोरदार वापसी से खेतों में लौटी जान, किसानों की जगी उम्मीदें

गंजबासौदा, देशबन्धु। आखिरकार कई दिनों के लंबे इंतजार के बाद गुरुवार को मानसून ने क्षेत्र में दमदार वापसी की। शहर सहित आसपास के ग्रामीण अंचलों में शाम से शुरू हुई झमाझम बारिश देर रात तक जारी रही। अच्छी बारिश से जहां मौसम सुहावना हो गया, वहीं खरीफ फसलों को नई संजीवनी मिलने से किसानों के चेहरे भी खिल उठे। पिछले एक सप्ताह से बारिश नहीं होने के कारण खेतों की मिट्टी सूखने लगी थी और किसान फसलों को लेकर गहरी चिंता में थे।

क्षेत्र में खरीफ सीजन की प्रमुख फसल सोयाबीन और उड़द इस समय बढ़वार के महत्वपूर्ण दौर में है। ऐसे समय बारिश का रुक जाना किसानों के लिए चिंता का विषय बन गया था। लगातार तेज धूप और उमस के कारण खेतों में नमी समाप्त होने लगी थी। इसका सीधा असर फसलों की वृद्धि पर पड़ रहा था। कई स्थानों पर पौधों की पत्तियां पीली पडने लगी थीं, जबकि बड़ी संख्या में

खेतों में इल्ली एवं अन्य कीट-पतंगों का प्रकोप बढ़ गया था। इल्लियां पत्तियों को तेजी से नुकसान पहुंचा रही थीं, जिससे उत्पादन प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई थी।

बारिश के बाद अब किसान फसलों में कीटनाशक दवाओं के छिडक़ाव की तैयारी कर रहे हैं। पर्याप्त नमी होने से दवाओं का प्रभाव बेहतर रहेगा और इल्ली व अन्य कीटों पर नियंत्रण पाने में मदद मिलेगी। किसानों का मानना है कि यदि अगले कुछ दिनों तक मानसून की गतिविधियां बनी रहीं तो फसलों की बढ़वार तेजी से होगी और उत्पादन में भी वृद्धि होगी।

फूफैर गांव के किसान तेजप्रताप सिंह राजपूत ने बताया कि पिछले कई दिनों से बारिश नहीं होने के कारण किसान बेहद चिंतित थे। खेतों में नमी खत्म हो रही थी और फसलों में कीट लगने लगे थे। गुरुवार को हुई जोरदार बारिश ने किसानों की चिंता दूर कर दी है। अब फसलों को पर्याप्त नमी मिलेगी और कीटनाशक दवाओं का छिडक़ाव भी प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा।

किसान सौरभ कुशवाह कहना है कि यह बारिश खरीफ सीजन के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। समय पर हुई वर्षा से फसलों की बढ़वार में तेजी आएगी, खेतों में हरियाली बढ़ेगी और अच्छी पैदावार की उम्मीद भी मजबूत हुई है। यदि आने वाले दिनों में भी मानसून इसी तरह सक्रिय रहा तो इस वर्ष किसानों को बेहतर उत्पादन और अच्छी आय मिलने की संभावना है। बारिश के बाद गांवों से लेकर शहर तक मौसम खुशनुमा हो गया और लोगों ने भी गर्मी व उमस से राहत महसूस की।

इल्लियां फसलों को पहुंचा रही नुकसान

गुरुवार शाम अचानक मौसम बदला और काले बादलों ने पूरे क्षेत्र को अपनी आगोश में ले लिया। कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई, जो रुक-रुककर देर रात तक होती रही। बारिश से खेतों में पर्याप्त नमी पहुंची और सूखती फसलों को नया जीवन मिला। किसानों ने इसे खरीफ सीजन के लिए सबसे राहत भरी बारिश बताया।

रक्षाबंधन से पहले बस किराया बढ़ा, यात्रियों में आक्रोश

सिरोंज, देशबन्धु। रक्षाबंधन से पहले बस किराए में हुई भारी बढ़ोतरी ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। परिवहन विभाग की नई दरें लागू होने के बाद बुधवार को बस स्टैंड पर दिनभर यात्रियों और बस स्टाफ के बीच किराए को लेकर बहस होती रही। महंगाई की मार पहले से झेल रहे लोगों का कहना है कि अब रोजमर्रा का सफर भी महंगा हो गया है। नई दरों के अनुसार बस किराया 1.25 रुपये प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर 2 रुपये प्रति किलोमीटर कर दिया गया है। इसका सीधा असर लंबी दूरी के यात्रियों पर पड़ा है। सिरोंज से भोपाल का किराया 150 रुपये से बढ़कर 220 रुपये और सिरोंज से गंजबासौदा का किराया 60 रुपये से बढ़कर 80 रुपये हो गया। अचानक बढ़े किराए से कई यात्री असमंजस में पड़ गए, जबकि कुछ लोगों ने अधिक किराया देने से इनकार कर बीच रास्ते में ही यात्रा छोड़ दी।

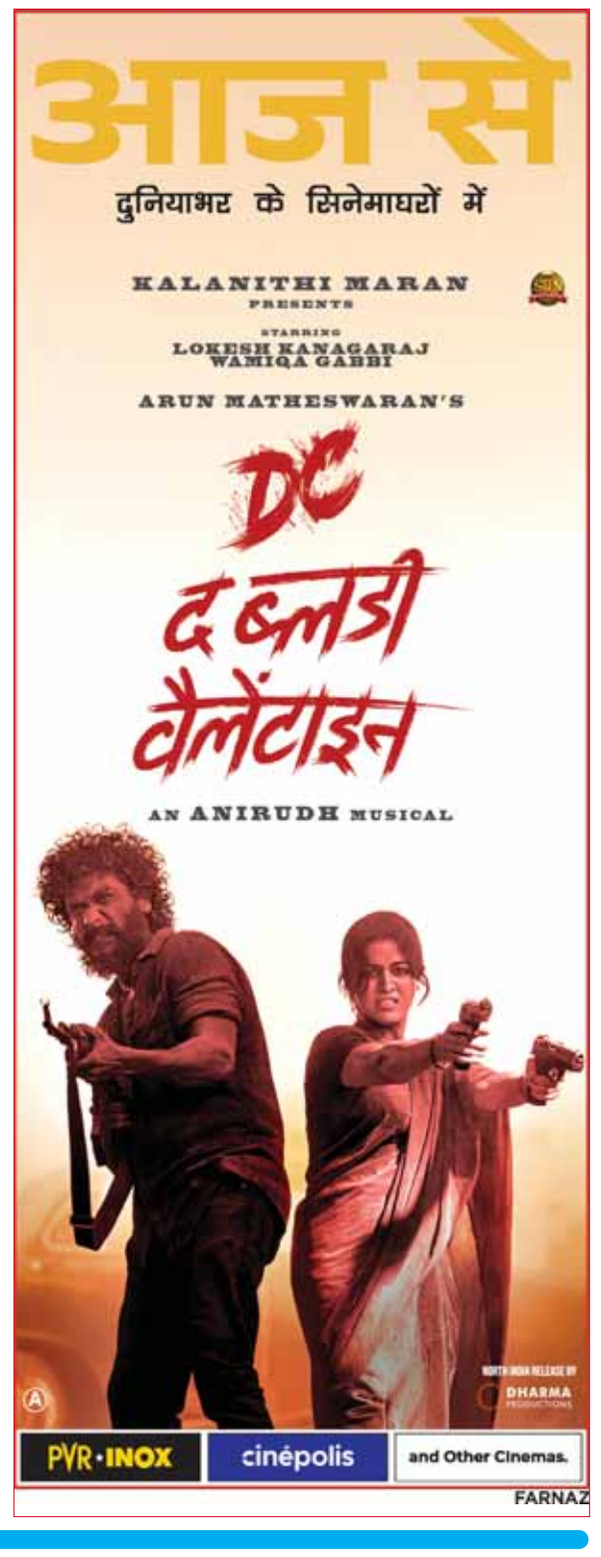

जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न

स्कूली बच्चों की सुरक्षा, अतिक्रमण हटाने और यातायात सुधार पर जोर

विदिशा, देशबन्धु। पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी एवं अपर कलेक्टर अनिल कुमार डामोर द्वारा गुरुवार को जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की। इस बैठक में पूर्व बैठकों के अनुपालन की समीक्षा करते हुए सड़क सुरक्षा से जुड़े विभिन्न एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा की गई तथा संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। सभी संबंधित विभागों को सड़क सुरक्षा के लिए समन्वय के साथ कार्य करने तथा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु निर्धारित कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए।

बैठक की शुरुआत 11 जून एवं 20 जुलाई 2026 को आयोजित जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण की समीक्षा से हुई। इसके बाद विदिशा नगरीय क्षेत्र में नवीन पाइपलाइन बिछाने के बाद क्षतिग्रस्त सड़कों के शीघ्र मरम्मत कार्य, जिला न्यायालय के सामने एवं शहर के प्रमुख चौराहों पर रंबल स्ट्रिप, रोड मार्किंग, साइन बोर्ड एवं कॉशन बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए। नगर पालिका ने जानकारी दी कि अधिकांश

स्थानों पर सड़क मरम्मत का कार्य पूरा कर लिया गया है तथा शेष स्थानों पर भी शीघ्र कार्य पूर्ण किया जाएगा। सभी स्थानों पर सीआरएम डालने का कार्य पूरा हो चुका है।बैठक में बताया गया कि पूर्व बैठक में निजी स्कूलों से संबद्ध बसों एवं ऑटो में विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे। इसके पालन में यातायात पुलिस द्वारा ऑटो चालकों को सुरक्षा मानकों के अनुरूप जाली एवं गेट लगाने के लिए लगातार समझाइश दी जा रही है। वाहन जांच अभियान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था नहीं पाए जाने पर 55 ऑटो चालकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई करते हुए 27,500 रुपये का शमन शुल्क वसूल किया गया।

नगर पालिका एवं यातायात पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा सड़क पर अवैध रूप से खड़े हाथ ठेलों तथा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है। नगर पालिका ने बताया कि पुलिस के सहयोग से अतिक्रमण हटाते हुए 1 लाख 97 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया। इसके अतिरिक्त सड़क किनारे एवं बीच सड़क पर ठेले और गुमठियां लगाकर व्यापार करने वालों के विरुद्ध विगत बैठक से अब तक लगभग 350 प्रकरण दर्ज कर करीब 2 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया है। बैठक में कुरवाई से महलुआ चौराहा मार्ग पर ओवरलोड वाहनों की रोकथाम के लिए एनएचएआई को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। साथ ही संकीर्ण पुलियों से 500 मीटर एवं 100 मीटर पहले चेतावनी संकेतक लगाने, दुर्घटना संभावित स्थलों पर पूर्व दुर्घटनाओं का चित्रण करने वाले बड़े फ्लेक्स लगाने तथा सभी निर्माण एजेंसियों को आवश्यक संकेतक स्थापित करने के निर्देश दिए गए। स्पीड ब्रेकर मानकों के अनुरूप बनाए जाने एवं एनएचएआई के सभी निर्माण कार्यों में उचित डायवर्सन और संकेतकों की व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा गया।

हाईमास्ट लाइट और ऑटो स्टैंड चिन्हांकन - पूर्व में चिन्हित स्थानों पर हाईमास्ट लाइट लगाने की समीक्षा के दौरान बताया गया कि इसके लिए निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। परिषद की स्वीकृति मिलने के बाद प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित स्थानों, विशेष रूप से कुआंखेड़ी चौराहे पर हाईमास्ट लाइट स्थापित की जाएगी।

संयुक्त समिति ने निरीक्षण में बताई थी खामियां

आरकेएमपी पर कचरा प्रबंधन में लापरवाही पर एनजीटी ने संबंधितों को लगाई फटकार

भोपाल,देशबन्धु। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन (आरकेएमपी) पर कचरा प्रबंधन में लापरवाही सामने आने पर राष्ट्रीय हरित अभिकरण (एनजीटी) ने संबंधितों को फटकार लगाई है। साथ ही सख्त निर्देश दिए हैं।

दरअसल कचरा प्रबंधन से जुड़े एक मामले को एनजीटी ने स्वत: संज्ञान में लिया था। इस मामले में संयुक्त जांच समिति ने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर निरीक्षण में कचरा प्रबंधन में कई खामियां बताई थीं। एनजीटी ने समिति की रिपोर्ट का अवलोकन करते हुए पाया कि निरीक्षण के दौरान रेलवे स्टेशन परिसर में कुछ स्थानों पर ठोस कचरे का संचय, पटरियों के किनारे कचरे की मौजूदगी और कचरा भंडारण क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता सामने आई। समिति ने रिपोर्ट में यह भी बताया था कि रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से संबंधित कचरा प्रबंधन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की जरुरत है। इस पर न्यायमूर्ति शिव कुमार सिंह, न्यायिक सदस्य सुधीर कुमार चतुर्वेदी की पीठ ने कहा कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का प्रभावी पालन आवश्यक है और पर्यावरण संरक्षण एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य की जिम्मेदारी संबंधित विभागों की है।

यह दिए निर्देश

एनजीटी ने मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) को ठोस कचरा प्रबंधन नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें और कचरे का निपटान नियमों के अनुसार करने और बंसल पाथवेज़ हबीबगंज प्राइवेट लिमिटेड को कचरे को उसके स्रोत पर ही अलग-अलग करें, तय रंग वाले चार तरह के कूड़ेदान की व्यवस्था, कचरा पैदा होने, इकट्ठा और निपटाने का रिकॉर्ड रखने के साथ ही रेलवे स्टेशन के कचरा भंडारण क्षेत्र को सुरक्षित, ढका हुआ और व्यवस्थित रखने, बिना इजाज़त किसी के अंदर आने पर रोक लगाने, कचरा इधर-उधर न फैलने देने के निर्देश दिए। इसके साथ ही रेलवे अथॉरिटी और संबंधित एजेंसी को मालगाड़ियों में मिलने वाले कचरे के स्रोत का पता लगाने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए निगरानी और नियंत्रण सिस्टम को मजबूत करने को कहा है। वहीँ डीआरएम और रेलवे बोर्ड को पर्यावरण के जानकार अधिकारियों के साथ एक पर्यावरण प्रकोष्ठ बनाने और ठोस कचरा प्रबंधन नियमों के अनुसार कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पर्यावरण नियमों के उल्लंघन के मामलों में ज़रूरी कार्रवाई करने, पर्यावरण से जुड़े नुकसान का हर्जाना वसूलें और सुधार के उपाय लागू करने के निर्देश दिए है। इसके आलावा डीआरएम और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दो महीने के अंदर एनजीटी मध्य क्षेत्र पीठ के रजिस्ट्रार के पास नियमों के पालन की रिपोर्ट जमा करने को कहा है।

गैस पीड़ितों के संगठनों ने किया दावा

बीएमएचआरसी के स्वास्थ्य केंद्रों में अब एक्स-रे सेवा बंद करने की तैयारी

भोपाल,देशबन्धु। यूनियन कार्बाइड गैस त्रासदी के पीड़ितों के साथ काम करने वाले चार संगठनों ने कहा कि भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (बीएमएचआरसी) ने अपने स्वास्थ्य केंद्रों (मिनी यूनिट्स) में महत्वपूर्ण पैथोलॉजी सेवाएं बंद कर दी हैं और अब वहां एक्स-रे सेवाओं को भी बंद करने की कोशिश की जा रही है, जिससे बुजुर्ग और बीमार गैस पीड़ितों को उनके घर के सबसे नज़दीक मिलने वाली मुफ्त स्वास्थ्य सेवा खत्म होती जा रही है।

भोपाल गैस पीड़ित महिला पुरुष संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष नवाब खान. भोपाल गैस पीड़ित महिला स्टेशनरी कर्मचारी संघकी अध्यक्ष रशीदा बी, भोपाल गैस पीड़ितनिराश्रित पेंशनभोगी संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष बालकृष्ण नामदेव, भोपाल ग्रुप फॉर इंफॉर्मेशन एंड एक्शन (बीजीआईए) की रचना ढींगरा ने कहा कि बीएमएचआरसी की सभी आठ मिनी इकाइयों में चल रही पैथोलॉजी प्रयोगशालाओं को गैस पीड़ितों से बिना किसी सलाह-मशविरे के बंद कर यहां के उपकरण और स्टाफ को मुख्य अस्पताल भेज दिया गया है। लिहाजा पहले जो जांच रिपोर्ट उसी दिन मिल जाती थी, अब उसमें 48 घंटे तक लग रहे हैं,और जिस दिन जाँच के नमूने लेने वाली अकेली नर्स उपलब्ध नहीं होती, मरीजों को वापस लौटा दिया जाता है। अब इसी तरह की कोशिश एक्स-रे सेवाओं के खिलाफ भी हो रही है। मिनी इकाई क्रमांक 1, 3, 5 और 8 में एक्स-रे फिल्म उपलब्ध नहीं कराई जा रही, मरीजों को मौखिक रूप से मुख्य अस्पताल जाने को कहा जा रहा है और इसके लिए न तो कोई लिखित आदेश जारी किया गया है और न ही कोई रिकॉर्ड रखा जा रहा है।

संगठनों ने कहा कि यह गैस पीड़ितों को मुफ्त और उचित स्वास्थ्य सेवा की गारंटी देने वाले सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन है, और इन आदेशों को लागू करने के बजाय, मौजूदा सेवाओं में कटौती करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। संगठनों ने इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के वरिष्ठ अधिकारियों और बीएमएचआरसी के निदेशक को पत्र लिखकर इन सेवाओं को तुरंत बहाल करने की मांग की है, और अलग से उच्चतम न्यायलय द्वारा नियुक्त निगरानी समिति के अध्यक्ष को भी पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।

सर्वोच्च न्यायालय में 11 अगस्त को उठेगा मुद्दा: रचना

भोपाल ग्रुप फॉर इंफॉर्मेशन एंड एक्शन (बीजीआईए) की रचना ढींगरा ने कहा गैस पीड़ितों के स्वास्थ्य को लेकर उच्चतम न्यायलय के आदेशों को लागू करने के बजाय, मौजूदा सेवाओं में कटौती की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इस मामले में बीजीआईए याचिकाकर्ता संगठन है। लिहाजा बीजीआईए 11 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध अवमानना याचिका में यह मुद्दा उठाएगा।

बीएमएचआरसी प्रबंधन ने कहा- सेवाओं का किया जा रहा है उन्नयन

उधर गैस पीड़ितों के संगठनों द्वारा दी गई जानकारी को बीएमएचआरसी प्रबंधन ने भ्रामक एवं तथ्यात्मक रूप से अधूरी बताया है। बीएमएचआरसी का कहना है कि संस्थान में मरीजों को बेहतर, सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभिन्न सेवाओं का निरंतर उन्नयन किया जा रहा है। पैथोलॉजी सेवाएं बंद नहीं की गई हैं। पहले की तरह स्वास्थ्य केंद्रों (मिनी यूनिट्स) में मरीजों के रक्त एवं अन्य आवश्यक नमूने लिए जा रहे हैं। परिवर्तन केवल इतना किया गया है कि इन नमूनों की जांच अब बीएमएचआरसी की मुख्य पैथोलॉजी प्रयोगशाला में स्थापित अत्याधुनिक एवं स्वचालित मशीनों पर की जा रही है। इसी तरह एक्स-रे सेवाएं बंद किए जाने संबंधी दावा भी पूरी तरह निराधार एवं भ्रामक है। बीएमएचआरसी के किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में एक्स-रे सुविधा समाप्त करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इसके विपरीत, स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध एक्स-रे सेवाओं को आधुनिक डिजिटल तकनीक से सुसज्जित करने की प्रक्रिया चल रही है।

अब रविवार को 15 मिनट में मिलेगी मेट्रो ट्रेन

भोपाल,देशबन्धु। भोपाल मेट्रो अब हर रविवार को 15 मिनट में यात्रियों को मिलेगी। रविवार और सार्वजनिक अवकाश के दिन मेट्रो 1 घंटा ज्यादा चलेगी। लोग रात 8.30 बजे तक मेट्रो में सफर कर सकेंगे।

मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने यात्रियों की सुविधा को और अधिक बढ़ाते हुए भोपाल मेट्रो के संचालन का विस्तार किया है। नई व्यवस्था के अनुसारख् रविवार एवं सार्वजनिक अवकाश के दिन सुभाष नगर स्टेशन से एम्स के लिए अंतिम मेट्रो शाम 7.30 बजे और एम्स स्टेशन से सुभाष नगर के लिए अंतिम मेट्रो रात 8 बजे रवाना होगी। 30 मिनट के अंदर मेट्रो पहुंच जाएगा। ऐसे में रात साढ़े आठ बजे तक मेट्रो का लुत्फ उठा सकेंगे। इससे यात्रियों को कम प्रतीक्षा समय के साथ शाम के समय भी अधिक सुविधाजनक मेट्रो सेवा उपलब्ध होगी। अन्य सभी कार्यदिवसों में मेट्रो का संचालन पूर्ववत रहेगा। इन दिनों भी व्यस्ततम समय सुबह 9 से 10.30 बजे तक और शाम 5.30 से शाम 7 बजे तक में यात्रियों को हर 15 मिनट के अंतराल पर मेट्रो सेवा उपलब्ध रहेगी, जबकि सुबह 10.30 से शाम 5.30 बजे तक में पूर्व निर्धारित समय-सारणी के अनुसार मेट्रो का संचालन किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि भोपाल मेट्रो में हाल ही में अत्याधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली के पूर्ण संचालन के बाद दोनों ट्रैक पर नियमित परिचालन प्रारंभ किया गया है, जिससे ट्रेन संचालन अधिक सुरक्षित, समयबद्ध एवं विश्वसनीय हुआ है। इसी क्रम में यात्रियों की बढ़ती संख्या एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए रविवार एवं सार्वजनिक अवकाश के लिए यह नई परिचालन व्यवस्था लागू की गई है।

पेंशनर्स जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

भोपाल,देशबन्धु। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), स्थानीय प्रधान कार्यालय द्वारा पेंशनभोगियों को नवीनतम पेंशन नियमों, साइबर सुरक्षा तथा बैंकिंग सेवाओं के संबंध में जागरूक करने के उद्देश्य से पेंशनर जागरूकता कार्यकम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक (साइबर) प्रणय कुमार नागवंशी, संयुक्त संचालक पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा विभाग अरविंद गुप्ता एवं एसबीआई के महाप्रबंधक लक्ष्मी नारायण,तथा वरिष्ठ नागरिक उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के प्रारम्भ में उप महाप्रबंधक जुल्फिकार अली खान, (कस्टमर एक्सपीरियंस) ने अतिथियों एवं पेंशनभोगियों का स्वागत करते हुए कार्यक्रम की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। वहीँ महाप्रबंधक भरत कुमार मिश्रा ने अपने संबोधन में कहा कि एसबीआई सदैव अपने पेंशनभोगी ग्राहकों को सुरक्षित, सरल एवं बेहतर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों से डिजिटल बैंकिंग सुविधाओं का सुरक्षित उपयोग करने तथा साइबर धोखाधड़ी से सतर्क रहने का कहा। सीपीपीसी के पंकज चतुर्वेदी ने पेंशन संबंधी विभिन्न सेवाओं, डिजिटल सुविधाओं, जीवन प्रमाण, शिकायत निवारण एवं अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत प्रस्तुति। इसके पश्चात पुलिस अधीक्षक प्रणय कुमार नागवंशी ने साइबर अपराधों से बचाव, ऑनलाइन धोखाधड़ी की पहचान तथा सुरक्षित डिजिटल लेनदेन के संबंध में उपयोगी जानकारी साझा की .इस अवसर पर चयनित वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम के समापन पर उप महाप्रबंधक सरत चंद्र पंडा ने आभार व्यक्त किया।

राजधानी में प्रशासनिक फेरबदल

निधि को एमपी नगर एसडीएम, पांडेय को उप जिला निर्वाचन अधिकारी का प्रभार

भोपाल,देशबन्धु। राजधानी में प्रशासनिक व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने कलेक्ट्रेट स्तर पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में फेरबदल किया है।

गौरतलब है कि संयुक्त कलेक्टर रहते एलके खरे लंबे समय से एमपी नगर एसडीएम थे। जुलाई में उनकी अपर कलेक्टर के रूप में पदोन्नति हुई थी। इस पर उनके कार्यमुक्त होने के बाद एसडीएम की कुर्सी खाली हो गई थी। अब यह जिम्मेदारी लंबे समय से कलेक्ट्रेट में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर निधि चौकसे को सौंपी गई है। उनके अधीन एमपी नगर, हरिजन कल्याण, अवधपुरी, बाग सेवनिया, क्राइम ब्रांच, अजाक्स, महिला थाना और जीआरपी थाना क्षेत्र आएंगे। इसके अलावा डिप्टी कलेक्टर एवं शहर वृत्त एसडीएम दीपक पांडेय को उप जिला निर्वाचन अधिकारी (डिप्टी डीईओ) की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दी गई है। वे निर्वाचन संबंधी कार्यों के साथ-साथ जनगणना कार्य का दायित्व भी संभालेंगे।

वहीं संयुक्त कलेक्टर एवं बैरागढ़ वृत्त एसडीएम रवीश कुमार श्रीवास्तव को भी कई अहम शाखाओं का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। उन्हें भू-संसाधन प्रबंधन, राहत एवं आपदा प्रबंधन, नजूल, आरआरसी, वक्फ प्रकरण, भू-अर्जन एवं मेट्रो परियोजना संबंधी कार्यों के साथ भूमि आवंटन शाखा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी तरह डिप्टी कलेक्टर लाखन चौधरी को प्रशासनिक निगरानी से जुड़ी महत्वपूर्ण शाखाओं का दायित्व सौंपा गया है। उनके पास अब सीएम हेल्पलाइन, समाधान आनलाइन, टीएल बैठक, जनसुनवाई, लोक सेवा प्रबंधन तथा सामान्य शिकायत शाखा का प्रभार रहेगा।

बैरसिया एसडीएम ने किया आईटीआई का निरीक्षण

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैरसिया सुश्री शिवांगी बघेल ने आईटीआई बैरसिया का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान संस्थान के प्राचार्य श्री अभिषेक श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान एसडीएम सुश्री बघेल ने संस्थान की शैक्षणिक एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं, प्रशिक्षण गतिविधियों, परिसर की स्वच्छता तथा उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं का अवलोकन किया। उन्होंने प्रशिक्षण की गुणवत्ता बनाए रखने तथा विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर संस्थान के प्राचार्य अभिषेक श्रीवास्तव ने संस्थान की गतिविधियों एवं उपलब्धियों की जानकारी प्रस्तुत की।

संविदा महिला कर्मचारियों को भी मिलेगी बच्चों की देखभाल के लिए छुट्टी

उच्च न्यायालय ने पूर्व आदेश की अवहेलना पर लगाया 50 हजार का जुर्माना

जबलपुर, देशबन्धु। उच्चतम न्यायलय और उच्च न्यायलय के स्पष्ट आदेशों के बावजूद संविदा महिला कर्मचारी को बच्चों की देखभाल की छुट्टी (चाइल्ड केयर लीव) सीसीएल से वंचित करना राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक हरजिंदर सिंह को महंगा पड़ गया। उच्च न्यायलय ने छुट्टी का आवेदन खारिज करने वाला विभागीय आदेश निरस्त करते हुए संचालक पर 50 हजार रुपये का व्यक्तिगत जुर्माना लगाया है।

न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता आयशा शेख की ओर से अधिवक्ता निखिल तिवारी ने पक्ष रखा। उन्होंने अवगत कराया कि याचिकाकर्ता नौवीं बार कोर्ट की शरण में है। इसी से प्रशासकीय मनमानी का अंदाजा लगया जा सकता है। राज्य शिक्षा केंद्र ने 16 जुलाई को आवेदन खारिज करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग के 22 जुलाई 2023 के परिपत्र का हवाला दिया था। विभाग का तर्क था कि बुरहानपुर निवासी संविदा कर्मचारी बच्चों की देखभाल छुट्टी की पात्र नहीं हैं। इस पर उच्च न्यायलय ने कहा कि मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियमए 1977 के नियम 38-सी में महिला सरकारी सेवक को 730 दिन तक बच्चों की देखभाल छुट्टी का प्रावधान है। संविदा महिला कर्मचारी भी दो बच्चों की देखभाल के लिए 240 दिन की छुट्टी की हकदार है। उच्च न्यायलय ने साफ किया कि न्यायालय कानून का व्याख्याकार है और उसकी व्याख्या अंतिम होती है। विभागीय परिपत्र न्यायिक आदेशों से ऊपर नहीं हो सकता। न्यायलय ने तत्काल छुट्टी देने और संचालक को 30 दिन में 50 हजार रुपये जमा करने के निर्देश दिये है।

डीएनए रिपोर्ट में कट पेस्ट की गलती पर 20 प्रतिशत रिपोर्टों की जांच के दिए आदेश

जबलपुर, देशबन्धु। मप्र उच्च न्यायलय ने डीएनए रिपोर्ट में कट पेस्ट के जरिए गलत नाम दर्ज होने के मामले को गंभीरता से लिया है। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल व न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने भोपाल स्थित राज्य फौरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की पिछले पांच वर्षों में तैयार डीएनए और अन्य वैज्ञानिक रिपोर्टों में से 20 प्रतिशत रिपोर्टों की रैंडम जांच कराने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही न्यायालय ने मुख्य सचिव को सात दिन के भीतर प्रदेश के बाहर के तीन वैज्ञानिक अधिकारियों की स्वतंत्र समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। समिति छह महीने में जांच पूरी करेगी। मामले की अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी। इस मामले कि सुनवाई के दौरान एफएसएल की प्रभारी निदेशक डॉ. हर्षा सिंह न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुईं। उन्होंने स्वीकार किया कि डीएनए रिपोर्ट में गलत नाम दर्ज होना कट पेस्ट की गलती के कारण हुआ हो सकता है। इस पर न्यायलय ने गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि यदि एक मामले में ऐसी त्रुटि सामने आई है तो यह जांचना जरूरी है कि अन्य रिपोर्टों में भी ऐसी गलती तो नहीं हुई। दरअसल, यह मामला नर्मदापुरम जिले के साकेत इटारसी निवासी पंकज कुमार बिंदोलिया की आपराधिक अपील से जुड़ा है। पंकज ने पाक्सो विशेष न्यायालय द्वारा 16 मार्च 2026 को सुनाई गई उम्रकैद की सजा को चुनौती दी है। सुनवाई में सामने आया कि 31 दिसंबर 2024 की एफएसएल रिपोर्ट में गलत व्यक्ति का नाम दर्ज था। न्यायलय ने एफएसएल निदेशक पद पर फॉरेंसिक साइंस, बायोलाजी या बायोकैमिस्ट्री जैसे संबंधित विषयों के विशेषज्ञ की नियुक्ति पर भी सरकार को गंभीरता से विचार करने के निर्देश दिए हैं।

महापौर ने किया पुलबोगदा क्षेत्र का निरीक्षण

भोपाल,देशबन्धु। महापौर श्रीमती मालती राय ने गुरूवार को बोगदापुल जिंसी क्षेत्र का निरीक्षण किया और मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के कार्यों के कारण परिवर्तित मार्ग पर आवागमन के संबंध में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, नगर निगम व ट्राफिक पुलिस के अधिकारियों, नागरिकों व व्यवसायियों से भी चर्चा की। महापौर श्रीमती राय ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बोगदापुल मार्ग पर आवागमन की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। महापौर श्रीमती राय ने अतिक्रमणों को हटाने तथा मार्ग को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। महापौर श्रीमती राय ने ट्राफिक पुलिस के अधिकारियों को भी यातायात की व्यवस्था को और अधिक सुचारू व बेहतर बनाने के निर्देश भी दिये। निरीक्षण के दौरान पार्षद श्रीमती नसीम गफूर, निगम, ट्राफिक पुलिस के अधिकारी व नागरिक मौजूद थे।

नाम परिवर्तन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं मोह. इलयास खान आयु वयस्क निवासी-234, लाल हाउसिंग कॉलोनी खुरई, तहसील खुरई, जिला सागर म.प्र. का हूँ। मेरे आधार कार्ड एवं पहचान पत्र में त्रुटिवश मेरा नाम मोहम्मद इलियास खान सिंह (MOHD. ISYAAS KHAN) दर्ज हो गया है जो कि गलत है। मेरा वास्तविक सही नाम पैन कार्ड में मोह. इलयास खान सिंह (MOHD. ILYASS KHAN) दर्ज होने से प्रमाणित है। मैं अपने वास्तविक सही नाम आधार कार्ड एवं पहचान पत्र में दर्ज करवाना चाहता हूँ। भविष्य में मेरा नाम मोह. इलयास खान (MOHD. ILYASS KHAN) के नाम से जाना पहचाना व पढ़ा जाये।

पुराना नाम	नया नाम
मोहम्मद इलियास खान सिंह (MOHD. ISYAAS KHAN)	मोह. इलयास खान (MOHD. ILYASS KHAN)

न्यायालय नायब तहसीलदार बैरागढ़ चीचली वृत तहसील कोलार भोपाल म.प्र.

प्रकरण क्रं. 1372/अ-6/26-27

इश्तहार

आवेदक सीमा दुबे पत्नी संजय दुबे निवासी ग्राम नयापुरा द्वारा ग्राम नयापुरा स्थित खसरा नंबर 25/26, व अन्य क्षेत्रफल 800 वर्गफिट का विक्रय पत्र/फौतर/वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतएव आवेदक के उपरोक्त आवेदन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति हो तो इस इश्तहार के जारी होने के दिनांक 12.08.2016 के भीतर इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। समयावधि पश्चात आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 05.08.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

अति. तहसीलदार
तहसील कोलार, जिला भोपाल

निरामय अस्पताल की सोनोग्राफी मशीन सील

भोपाल,देशबन्धु। गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीकी (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम के उल्लंघन पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) एवं समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी एक्ट द्वारा निरामय अस्पताल की सोनोग्राफी मशीन को सील किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सीएमएचओ कार्यालय के दल ने गुरुवार को निरामय अस्पताल में किए गए नियमित निरीक्षण के दौरान फॉर्म एफ में गंभीर अनियमितता मिली थीं। फॉर्म में कुछ गर्भवती महिलाओं की प्रविष्टी मिली लेकिन एएनसी रजिस्टर में उनकी प्रविष्टि नहीं की गई। फॉर्म एफ में परीक्षण और परिणाम का उल्लेख नहीं किया गया। निरीक्षण के दौरान कुछ फॉर्म में मरीज के नाम के अलावा अन्य कोई भी प्रविष्टि नहीं पाई गई । फार्म में अपूर्ण जानकारी भरने पर गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीकी (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम के तहत आगे की कार्यवाही की जाएगी। इसके तहत अस्पताल संचालक डॉ.अखिलेश मोहन लहरी एवं रेडियोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ मिश्रा को नोटिस जारी कर दोनों के खिलाफ न्यायालय में परिवाद दायर किया जा रहा है।

समायावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में संभाग आयुक्त ने कहा-

मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान का समुचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करें

भोपाल,देशबन्धु। संभागायुक्त कर्मवीर शर्मा ने कहा है कि सभी संभागीय अधिकारी, मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान में शामिल हों एवं नियत प्रारूप में प्रतिवेदन तैयार कर संभागायुक्त को प्रस्तुत करें। श्री शर्मा ने यह निर्देश समय - सीमा की बैठक में दिए।

संभागायुक्त श्री शर्मा ने मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान का उद्देश्य क्षेत्र भ्रमण, निरीक्षण एवं जन संवाद के माध्यम से आम जनता की शिकायतों का त्वरित निराकरण, शासकीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन और लोक सेवाओं को समय-सीमा में प्रदाय करना है। लिहाजा सभी विभागीय अधिकारी अपने जिले में सतत भ्रमण कर लंबित सीएम हेल्पलाइन शिकायतों का निराकरण, लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत समय-सीमा से बाहर के लंबित प्रकरणों का निराकरण, विभागीय संस्थाओं का निरीक्षण तथा विभागीय योजनाओं की गहन समीक्षा करना सुनिश्चित करें। श्री शर्मा ने कहा कि जन-विश्वास अभियान अंतर्गत सम्मिलित किये गए 20 प्रमुख विषयों पर सघन कार्यवाही और शासकीय संस्थाओं आदि का निरीक्षण किया जाएगा। इसमें नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा के मामले, किसानों की फार्मर आईडी, आयुष्मान कार्ड, समग्र ई-केवाईसी, प्रधानमंत्री आवास योजना, और जल जीवन मिशन की समीक्षा शामिल है। इसके अलावा आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल-कॉलेज, राशन दुकान, खाद-बीज की उपलब्धता, कानून व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी जनहितकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का मैदानी स्तर पर पर्यवेक्षण किया जाएगा। बैठक में संभागायुक्त श्री शर्मा ने सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों की समीक्षा करते हुए 50 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों के निराकरण के लिए विभागों को माइक्रो स्तर पर प्लानिंग कर संतुष्टिपूर्वक निराकरण करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम के लिए संभाग स्तरीय समिति का गठन करने के निर्देश दिए गए।

पहला जन विश्वास शिविर आज

मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान अंतर्गत शुक्रवार प्रात: साढ़े 8 बजे से वार्ड क्रमांक 47, श्याम नगर, लिंक रोड न.3 जोनल क्रमांक-6 में प्रथम जन विश्वास शिविर का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने सभी एसडीएम एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए है कि शिविर में सीएम हेल्पलाइन पोर्टल, जनसुनवाई एवं लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले आवेदनों की समीक्षा कर एवं पूर्व में प्राप्त आवेदनों का निराकरण सुनिश्चित करें।

MUNICIPALCOUNCIL ASHOKNAGAR, M. P.

Email cmoashoknagar@mpurban.gov.in, Ph 07543-222811

Request for Proposal

Tender-ID-2026-UAD-525769-1

No.4949/2026/ Ashoknagar Dated:-28.07.2026

at Proposals are invited from qualified & experienced firms for selection of a Project Management Consultant (PDMC) for implementation of water augmentation supply project at Ashoknagar ULB. Information Document cum RFP form can be downloaded from Website: http://mpetender.gov.in while submitting downloaded docket a Tender Fees of Rs. 10000.00 (Rs. Ten thousand only) in payable at portal only.. Proposal along with required documents as specified in the information Docket cum RFP form shall submitted portal by 31.08.2026, 5.30 Etender only, latest pm.. Modifications/Amendments/Corrigendum, in RFP if any shall not be advertised in the news paper but shall be published in the web site only. The under signed reserve the right to change the terms and conditions, select/reject any application without assigning any reasons there of.

Chief Muniepal Officer
Municipal Council Ashoknagar
Ashoknagar Madhya Pradesh

समृद्ध किसान समृद्ध प्रदेश
किसान कल्याण वर्ष 2026

बलराम कृषि महोत्सव

15 जुलाई से 13 नवंबर 2026

अन्नदाता का सम्मान, आधुनिक कृषि के नवाचार और प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक ही मंच पर समागम

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

भोपाल संभाग में महोत्सव

सीहोर	राजगढ़	भोपाल	रायसेन	विदिशा
7 अगस्त	9 अगस्त	11 अगस्त	13 अगस्त	16 अगस्त

मुख्य अतिथि

डॉ. मोहन यादव

मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

- किसान और संवाद
- सम्मान का गौरवपूर्ण मंच
- आधुनिक कृषि का प्रदर्शन
- कृषि और संस्कृति का संगम

किसानों के हित में विभागों द्वारा कार्य

- 490 लाख मीट्रिक टन उद्यानिकी उत्पादन का लक्ष्य
- 4 गुना मुआवजा कृषि भूमि अर्जन पर
  ₹12 हजार पीएम किसान सम्मान एवं मुख्यमंत्री किसान कल्याण में सालाना
- 10 हॉर्सपावर तक ऊर्जा प्रभार में सब्सिडी
  ₹5 में बिजली का स्थाई कनेक्शन
- 60% खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहन
- 50 लाख लीटर प्रतिदिन दुग्ध संकलन का लक्ष्य
- 5,562 दुग्ध समितियों के माध्यम से
  83 हजार सदस्यों का वित्तीय समावेशन
- 0% ब्याज दर पर फसल ऋण, भुगतान हेतु साल भर की सुविधा
- 32 लाख किसानों को पीएम कुसुम योजना सोलर पंप का लक्ष्य
- स्वरोज़गार को बढ़ावा महिला एवं ग्रामीण युवा जुड़ेंगे कुटीर उद्योगों से
- 1000 होम-स्टे बनाने का लक्ष्य ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहन
- जागरुकता का प्रसार कृषक कल्याणकारी कार्यक्रमों का
- 100 लाख हेक्टेयर सिंचाई को वर्ष 2028-29 तक करने का लक्ष्य
- वित्त पोषण नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स से सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार
- संस्कृति को प्रोत्साहन श्री अन्न, ग्रामीण व्यंजन एवं स्थानीय परम्पराओं को प्रोत्साहन
- 50% तक सब्सिडी कृषि आधारित उद्योगों को
- ₹6000 करोड़ के मत्स्य निर्यात का लक्ष्य
- ₹12,400 करोड़+ का संभावित निवेश

सीधा प्रसारण @Cmmadhyapradesh @jansampark.madhyapradesh @Cmmadhyapradesh @jansamparkMP JansamparkMP

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी

D-11072/26